https://www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

सभी देश आतंकवाद से निपटने के लिए समग्र रुख अपनाए

वर्ष-12, अंक-18, 16-30 सितंबर, 2017 (पाक्षिक) ₹20

ओडिशा में मिशन 120+ का शुभारंभ

'स्वच्छता ही सेवा' की मुहिम चलायें: नरेंद्र मोदी

जन धन योजना और एक अरब-एक अरब-एक अरब 'जैम' क्रान्ति का शुभारंभ

ऐसे होगी किसानों की आमदनी दोगुनी

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के ओडिशा 'विस्तृत प्रवास' के चित्र

मुम्बई में जनाभिवादन स्वीकार करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

लालबागचा, मुम्बई में भगवान गणेश का आशीर्वाद लेते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

नई दिल्ली में नॉर्थ–ईस्ट डेमोक्रेटिक अलाइंस की दूसरी बैठक के अवसर पर पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in
mail@kamalsandesh.com

वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **ओडिशा सरकार का विकास रूपी ट्रांसफॉर्मर जल चुका है, उखाड़ कर फेंक दीजिए : अमित शाह**

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 6 सितम्बर को 'संकल्प से सिद्धि' कार्यक्रम के तहत होटल पाल हाइट्स, भुबनेश्वर (ओडिशा) में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया और...

वैचारिकी

भारतीय जनसंघ की अर्थ नीति 14

श्रद्धांजलि

पंडित दीनदयाल उपाध्याय 16

लेख

जन धन योजना और एक अरब-एक अरब-एक अरब 'जैम' 19

शासन संचालन में उदाहरणीय परिवर्तन 23

अन्य

2400 मीट्रिक टन आयातित प्याज पहुंची 13

4 राज्यमंत्रियों को कैबिनेट मंत्री और 9 नए राज्यमंत्री बनाए 17

एनडीए सरकार की पहुंच और कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट निर्णय... 19

ऐसे होगी किसानों की आमदनी दोगुनी 21

सभी देश आतंकवाद से निपटने के लिए समग्र रुख अपनाए 25

भारत और म्यांमार के बीच कुल हुए 11 समझौते 28

'स्वच्छता ही सेवा' की मुहिम चलायें: नरेंद्र मोदी 30

नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस (नेडा) : द्वितीय परिषद् बैठक 31

पत्र-पत्रिकाओं से... 32

संगठनात्मक गतिविधियां

08 **'नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा फिर से बहाल की'**

''गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पूर्व श्री नरेन्द्र मोदी कभी भी किसी कालेज...

10 **गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश एवं मेघालय प्रदेश चुनाव प्रभारियों की घोषणा**

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष...

सरकार की उपलब्धियां

11 **1.40 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ अब तक 26 लाख से अधिक मकानों की मंजूरी**

शहरी इलाकों में सस्ते मकानों के निर्माण में...

12 **अटल पेंशन योजना 62 लाख नामांकन के साथ प्रगति की ओर अग्रसर**

एक राष्ट्र-एक पेंशन के अंतर्गत कुल 3.07 लाख अटल पेंशन योजना (एपीवाई) खाते हो गए हैं...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

भारत गांधी जी और भगवान बुद्ध की भूमि है। हिंसा हमारी संस्कृति में नहीं है। हिंसा का कोई भी रूप स्वीकार्य नहीं है।

@AmitShah

परिवारवाद पर आधारित पार्टियों का ना कोई सिद्धांत है,ना देश को आगे बढ़ाने का एजेंडा है और ना ही देश की नीतियों को प्रभावित करने का माद्दा।

@VasundharaBJP

बाढ़ के दौरान हुई जनहानि, पशुधन की क्षति एवं मकानों के नुकसान के लिए प्रदेश में पहली बार SDRF द्वारा सहायता राशि दी गयी है।

@rsprasad

जन धन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 17 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोल दिए गए हैं।

facebook

योजनाबद्ध तरीके से प्रयास कर किसानों की आय बढ़ायी जा सकती है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिये मिशन मोड में काम करें। यह किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगा। पशुओं की गुणवत्ता में सुधार का अभियान चलायें। दुग्ध उत्पादन वृद्धि से किसानों को फायदा दिलायें। मत्स्य-उत्पादन के माध्यम से मछुआरों की आय बढ़ाने के प्रयास करें। रेशम उत्पादन के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करें। प्रदेश में सिंचाई के लिए बिजली की कमी नहीं हो, यह सुनिश्चित करें। — **शिवराज सिंह चौहान**

केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाले अनुदान के अतिरिक्त खुद के संसाधनों द्वारा विकास करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ अग्रणी है। मेरा विश्वास है कि आने वाले सालों में हमारा प्रदेश लॉजिस्टिक हब बन कर उभरेगा और #NewChhattisgarh के रूप में अपनी नई पहचान बनाएगा। — **डॉ. रमन सिंह**

क्या आप जानते हैं? 17 लाख किसानों की फसल का बीमा झारखंड सरकार ने करवाया है, ताकि किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा से उनका आर्थिक नुकसान न हो। — **रघुबर दास**

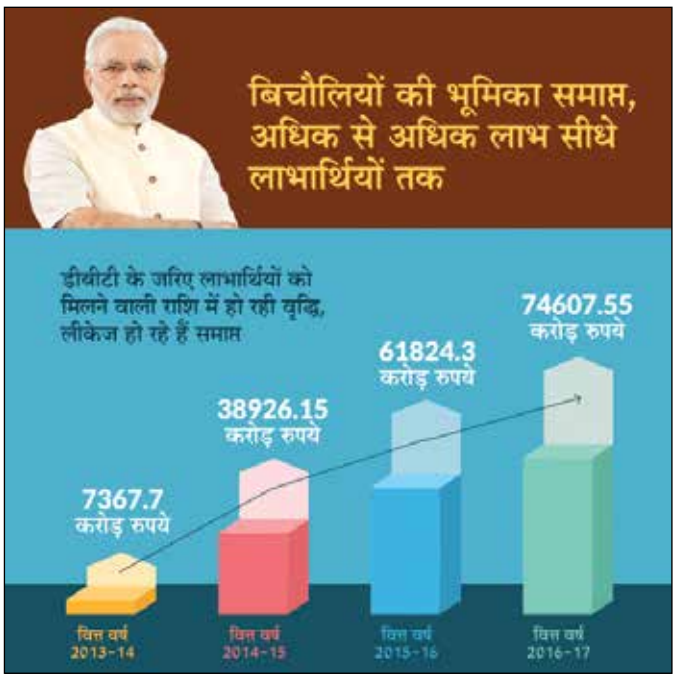

कांग्रेस झूठ, फरेब और छलावे की राजनीति से अपनी किस्मत नहीं बदल सकती

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों झूठ, फरेब और छलावे की राजनीति में कम्युनिस्टों को भी पीछे छोड़ने में लगे हैं। इस कला में महारत हासिल करने के लिए जहां वे आधारहीन आरोपों को लगाने से नहीं चूक रहे, वहीं अपने कुतर्कों की कोई जिम्मेदारी लेने से वे भी कतरा रहे हैं। लगता है कांग्रेस समझ नहीं पा रही कि कम्युनिस्टों को पीछे छोड़ने के चक्कर में उनका ग्राफ हर दिन नीचे गिरता जा रहा है। एक ओर जहां लोगों ने कम्युनिस्टों को दोहरा चरित्र तथा झूठ एवं घृणा की राजनीति के लिये उन्हें राजनीति से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, वहीं दूसरी ओर लगता है यदि राहुल गांधी भी इसी तरह कम्युनिस्टों से पाठ पढ़ते रहे हैं तो कांग्रेस की भी गत यही होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा पर जितने भी निराधार आरोप अब तक राहुल गांधी ने लगाये हैं, देश की जनता ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसकी संभावना कम ही है कि राहुल गांधी के आरोपों को लोगों द्वारा लगातार ठुकराये जाने पर भी वे इससे कोई सीख ले पायेंगे। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने नेता के ऐसे आधारहीन आरोपों का कांग्रेस पार्टी के पास समर्थन करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। चुनावों में लगातार हार तथा हाशिये पर चले जाने से कांग्रेस में भारी कुंठा का निर्माण हुआ है, जिसके फलस्वरूप भाजपा के विरुद्ध कांग्रेस नेतृत्व उटपटांग रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस को अब भी समझ लेना चाहिए कि वह केवल ईमानदार आत्ममंथन कर देश सेवा, समर्पण एवं गरीब एवं वंचितों के हित में कार्य कर ही राजनीति में सकारात्मक भूमिका निभा सकती है। सिद्धांतहीन, अवसरवादी एवं सत्ता केंद्रित राजनीति के दलदल में फंसी कांग्रेस झूठ, फरेब एवं छलावे की राजनीति से अपनी किस्मत नहीं बदल सकती। इससे कांग्रेस का देश की राजनीति में दिनोंदिन हाशिए पर जाना तय है।

आज जब भारत तेजी से सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहा है, झूठ एवं छलावे की राजनीति बार-बार पराजित हो रही है। आत्मविश्वास से भरे भारत को दुनिया ने हाल ही में संपन्न ब्रिक्स सम्मेलन में देखा, जहां आतंकवाद के विरुद्ध भारत के पक्ष पर सदस्य देशों ने अपनी मुहर लगाई तथा पाकिस्तान से संचालित आतंकी गुटों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

इस बात को लगभग अब हर कोई समझ चुका है कि जब भी देश में कोई घटना घटती है, तब मीडिया का एक वर्ग कुछ तथाकथित 'सेकुलर-लिबरल-कम्युनिस्टों' के सुर में सुर मिलाकर क्यों भाजपा को निशाने पर लेती हैं। जब से देश ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भारी जनादेश दिया है तथा भाजपा की सरकार केन्द्र में बनी है, यह वर्ग आकुल-व्याकुल हो रहा है। लोग अब तक 'अवार्ड वापसी' और 'असहिष्णुता' के ईद-गिर्द बुनी उस भ्रामक प्रचार को नहीं भूल पाये हैं, जिसका अब कोई नामलेवा नहीं बचा है। बिना किसी पुख्ता तथ्य के आधार पर भाजपा को घेरने की इस वर्ग की कोशिश कई बार औंधे मुंह गिर चुकी है और इनकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। साथ ही यह भी चिंताजनक है कि भारतीय राजनीति में बिना किसी प्रमाण के आरोप गढ़ने का चलन तेज हो गया है।

कर्नाटक में गौरी लंकेश की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से की गई हत्या उनके वैचारिक सहयोगियों के लिए भाजपा/संघ के विरुद्ध प्रोपगंडा करने का एक राजनैतिक अवसर बन गया। जहां कर्नाटक सरकार के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाये गये, वहीं इस हत्या को राजनैतिक तौर पर भुनाने की भरपूर कोशिश हुई। आधारहीन एवं झूठे आरोपों पर राजनैतिक गोटियां खेलने वाले इस वर्ग के मंसूबे अनेक बार जनता ने ध्वस्त किये हैं तथा इनके चेहरे अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। फलस्वरूप आज न केवल ये राजनीति से दरकिनार कर दिये गये हैं, बल्कि बार-बार मुंह की खाकर अब हाशिए पर अपना भविष्य तलाश रहे हैं।

आज जब भारत तेजी से सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहा है, झूठ एवं छलावे की राजनीति बार-बार पराजित हो रही है। आत्मविश्वास से भरे भारत को दुनिया ने हाल ही में संपन्न ब्रिक्स सम्मेलन में देखा, जहां आतंकवाद के विरुद्ध भारत के पक्ष पर सदस्य देशों ने अपनी मुहर लगाई तथा पाकिस्तान से संचालित आतंकी गुटों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। डोकलाम विवाद से भी भारत मजबूत होकर निकला है तथा कश्मीर में अलगाववादी निरंतर अलग-थलग पड़ते जा रहे हैं। सरकार जीएसटी जैसे बड़े आर्थिक सुधारों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर भारत को 2022 के 'न्यू इंडिया' की ओर ले जाने को कृतसंकल्पित है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा भाजपा को मिल रहे अपार जनसमर्थन से कांग्रेस और इसके सहयोगियों के हाथ-पांव फूल रहे हैं। जहां कांग्रेस का अब भी झूठ-छलावे और प्रोपगंडा की राजनीति पर अटूट विश्वास है, वहीं इसके कम्युनिस्टों के साथ तालमेल इसके लिये राजनैतिक रूप से आत्मघाती आत्महत्या जैसा कदम साबित हो रहा है। जब तक कांग्रेस इस सच्चाई को समझेगी नहीं, इसे अपने अवश्यंभावी पतन से कोई नहीं बचा सकता। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

ओडिशा सरकार का विकास रूपी ट्रांसफॉर्मर जल चुका है, उखाड़ कर फेंक दीजिए : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 6 सितम्बर को 'संकल्प से सिद्धि' कार्यक्रम के तहत होटल पाल हाइट्स, भुबनेश्वर (ओडिशा) में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, सिद्धांतों एवं कार्यपद्धति पर विस्तार से चर्चा की। विदित हो कि श्री शाह देश के सभी राज्यों में कुल 110 दिनों के अपने विस्तृत प्रवास कार्यक्रम के तहत तीन दिवसीय दौरे पर ओडिशा प्रवास पर थे।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि एक बहुदलीय लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली में किसी भी पार्टी का मूल्यांकन तीन मापदंडों के आधार पर किया जाना चाहिए - पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र, पार्टी का सिद्धांत और सत्ता में आने पर सरकार की कार्यपद्धति। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि देश की जनता इन आधारभूत मापदंडों पर राजनीतिक पार्टियों का मूल्यांकन करे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी पार्टियों से अलग है, क्योंकि आज देश में मौजूद लगभग 1650 छोटी-बड़ी पार्टियों में से केवल भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके अंदर आतंरिक लोकतंत्र बचा हुआ है।

श्री शाह ने कहा कि किसी भी दल का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए दूसरा सबसे महत्त्वपूर्ण मापदंड है - पार्टी का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि सिद्धांतों के आधार पर वही पार्टियां चल सकती हैं, जो वंशवाद के आधार पर नहीं चलती।

उन्होंने कहा कि 1950 से 2017 की जन संघ से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा अंत्योदय, एकात्म मानववाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की यात्रा रही है और यही हमारे मूल सिद्धांत हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ओडिशा में विकास की संभावना गुजरात से सौ प्रतिशत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि गुजरात में विकास के व्यापक कार्य हुए हैं, लेकिन ओडिशा में विकास की संभावनाओं को एक्सप्लोर करने के बजाय केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि ओडिशा में बीजद सरकार विकास नहीं कर सकती, यह परफॉरमेंस करने वाली सरकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जो सरकार परफॉर्म नहीं कर सकती, विकास नहीं कर सकती, उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि आप भाजपा और शेष पार्टियों की सरकारों की तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहां-जहां भाजपा की सरकार है, वहां तेज गति से विकास होता है। उन्होंने कहा कि जो आजादी के 65 साल बाद तक देश में विकास नहीं कर पाए, उनके विकास के वादे पर आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस और बीजद ने विकास योजनाओं पर आजादी के बाद से अब तक काम किया होता तो हमें इन कामों को पूरा करने का पुण्य नहीं मिलता।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश के विकास व गरीब-कल्याण के लिए लगभग 106 योजनाओं की शुरुआत की है और इनमें से एक भी योजना ऐसी नहीं है जो किसी एक जो किसी एक वर्ग विशेष के लिए बनी हो। ये सभी योजनायें सर्वस्पर्शी एवं सर्व समावेशी हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इन सभी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सफल रही है। 104 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर भारत अंतरिक्ष के अंदर दुनिया की एक प्रमुख ताकत के रूप में उभरा है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश के लगभग पौने तीन करोड़ गरीब महिलाओं के घर में गैस सिलिंडर पहुंचाया गया है, साढ़े चार करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण कर महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया गया है और लगभग 29 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खोल कर उन्हें देश के अर्थतंत्र की मुख्यधारा में जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी देश की 60% आबादी का देश के अर्थतंत्र के साथ जुड़ाव ही नहीं था। मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से देश के करोड़ों गरीब युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गए हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जीएसटी के रूप में 'एक राष्ट्र, एक कर' का स्वप्न साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी, बेनामी संपत्ति क़ानून, शेल कंपनियों के खिलाफ अभियान और मॉरीशस-साइप्रस-सिंगापुर रूट को बंद करके काले-धन पर कठोर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने योग को पूरी दुनिया में स्वीकृति दिला कर देश की संस्कृति को प्रतिष्ठित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के जरिये आतंकवाद पर करारा प्रहार किया, इससे दुनिया का देश को देखने का नजरिया बदल गया। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी बिजली से वंचित लगभग 19 हजार गांवों में से साढ़े 13 हजार से अधिक गांवों में बिजली पहुंचा दी गई है, बचे हुए गांवों में भी मई, 2018 तक पहुंचा दी जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा, स्वायल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, सिंचाई योजना, ई-मंडी जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय को 2022 तक दुगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेज गति से काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि

भाजपा का मिशन 120+

ओडिशा भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधान सभा चुनाव में प्रदेश में 120 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने नवीन पटनायक को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें गिनती सीख लेनी चाहिए, भाजपा 120 से अधिक सीटें जीत कर दो तिहाई बहुमत से ओडिशा में सरकार बनाने जा रही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूरी दुनिया में योग को प्रतिष्ठित कर भारतीय संस्कृति और धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत दिलाई। उन्होंने कहा कि डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए भीम एप सबसे पॉपुलर प्लेटफ़ॉर्म है। उन्होंने कहा कि जब श्री नरेन्द्र मोदी के रूप में गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनता है तब इस तरह की गरीब-कल्याण की सोच विकसित होती है और प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास के स्केल को ऊपर उठाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा से अधिक प्रायोरिटी किसी और चीज की इस सरकार की नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश को स्वच्छता का संस्कार देने का काम किया है, हमने देश को परिवर्तित करने का प्रयास है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि ओडिशा के विकास के लिए पिछले तीन साल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कई कार्य किये हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ओडिशा के विकास के लिए यूपीए के 13वें वित्त आयोग की तुलना में 14वें वित्त आयोग में लगभग ढाई गुना अधिक राशि दी है। उन्होंने कहा कि 13वें वित्त आयोग में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने ओडिशा को विकास के लिए 79,486 करोड़ रुपये की राशि दी थी, जबकि 14वें वित्त आयोग में मोदी सरकार ने राज्य के लिए 2,11,510 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। इसके अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं के लिए राज्य को 40,000 करोड़ रुपये की राशि अलग से उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए ओडिशा को दिया गया पैसा आखिर गया कहां, इसका हिसाब नवीन पटनायक जी को देना चाहिए, आप उनसे हिसाब मांगें या न मांगें, मैं तो जरूर मांगूगा।

उन्होंने कहा कि ओडिशा सरकार का विकास रूपी ट्रांसफॉर्मर जल चुका है, उखाड़ कर फेंक दीजिए ओडिशा की इस निकम्मी एवं भ्रष्ट बीजद सरकार को। इस सरकार के रहते ओडिशा का विकास हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि ओडिशा में यदि विकास चाहिए तो राज्य में एक ऐसी सरकार बनानी होगी जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर राज्य के विकास के लिए काम करे। उन्होंने कहा कि आपने सबको मौक़ा देकर देख लिया है, आपने कांग्रेस को मौक़ा दिया है, बीजद को मौक़ा दिया, आप एक मौक़ा भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, हम ओडिशा को देश के विकसित राज्यों में शुमार करेंगे। ■

'नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा फिर से बहाल की'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं, परन्तु विरोधी तक भी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सके हैं। मोदी जी ने जाति, परिवार प्रभुत्व, तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति की जगह पूरे देश में परफॉर्मेंस की राजनीति को मुख्यधारा से जोड़ा है।

मुम्बई के एक दिन के प्रवास के दौरान 27 अगस्त, 2017 को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह बांद्रा के गणेश मंडल, लालबागचा राजा गणेश मंडल गए और वहां उन्होंने नरीमन प्वाइंट पर एकत्र हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया। श्री शाह ने कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा– ''श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं, परन्तु विरोधी तक भी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सके हैं।"

श्री शाह ने प्रधानमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने जाति, परिवार प्रभुत्व, तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति की जगह पूरे देश में परफॉर्मेंस की राजनीति को मुख्यधारा से जोड़ा है।

श्री शाह ने पूर्व कांग्रेस–नीत यूपीए सरकार के 12 लाख करोड़ से भी अधिक घोटालों की घोर निंदा की। उन्होंने कहा कि मोदी जी

के परिवार ने कभी भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया। ऐसे कुछ ही नेता होते हैं जो अपने निजी जीवन में इतने उच्च शुचिता के स्तर पर रह पाते हैं।

मनमोहन सिंह सरकार में प्रत्येक मंत्री अपने आपको प्रधानमंत्री समझता था और प्रधानमंत्री को किसी ने प्रधानमंत्री नहीं समझा। श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को पुनः बहाल किया। उन्होंने कहा कि यह सरकार निर्णायक, पारदर्शी, गतिशील और भरोसेमंद सरकार है।

श्री शाह ने कहा कि सरकार-निर्माण का कार्य बहुत सरल है परन्तु एक आम आदमी को पार्टी कार्यकर्ता में परिवर्तित करना मुश्किल कार्य होता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हजारों कार्यकर्ताओं का निर्माण किया और संगठन की गरिमा को बढ़ाया।

श्री मोदी के कार्यों की सराहना करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पूर्व श्री नरेन्द्र मोदी कभी भी किसी कॉलेज चुनाव या किसी ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव नहीं जीते थे। उनके पास किसी प्रकार का अनुभव नहीं था, परन्तु अपनी श्रद्धा, कठिन परिश्रम और वचनबद्धता के बल पर उन्होंने भाजपा को अजेय पार्टी बना दिया। श्री मोदी ने बूथ–स्तरीय पार्टी कार्यकर्ताओं के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया।

श्री शाह ने कहा कि जब पिछली सरकार भ्रम में थी कि कृषि नीति को बढ़ावा दिया जाए या उद्योगों एवं गरीबों के हित में सुधार लाने के लिए कल्याणकारी कदम उठाए जाएं, तो मोदी जी ने कृषि सेक्टर की नीति को क्रियान्वित किया और उद्योगों को बढ़ावा दिया और साथ ही नीतियों में भी सुधार लाया।

उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी ने राजनीति का स्तर बदल दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को बढ़ाया, जो डा. सिंह के समय में खो गई थी।

गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पूर्व श्री नरेन्द्र मोदी कभी भी किसी कॉलेज चुनाव या किसी ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव नहीं जीते थे। उनके पास किसी प्रकार का अनुभव नहीं था, परन्तु अपनी श्रद्धा, कठिन परिश्रम और वचनबद्धता के बल पर उन्होंने भाजपा को अजेय पार्टी बना दिया। श्री मोदी ने बूथ–स्तरीय पार्टी कार्यकर्ताओं के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया।

श्री अमित शाह ने आगे कहा कि यह विकास की राजनीति के परिवर्तन की शुरुआत थी, जिसके कारण मोदी जी विश्व के राजनेता बन गए। विश्व भर के देशों में मोदी जी के भाषण का सम्मान हुआ, यह भाजपा या मोदी के सम्मान की बात नहीं थी, बल्कि यह भारत के 125 करोड़ लोगों का सम्मान था। ■

'हमारे नरेन्द्र मोदी' पुस्तक का विमोचन

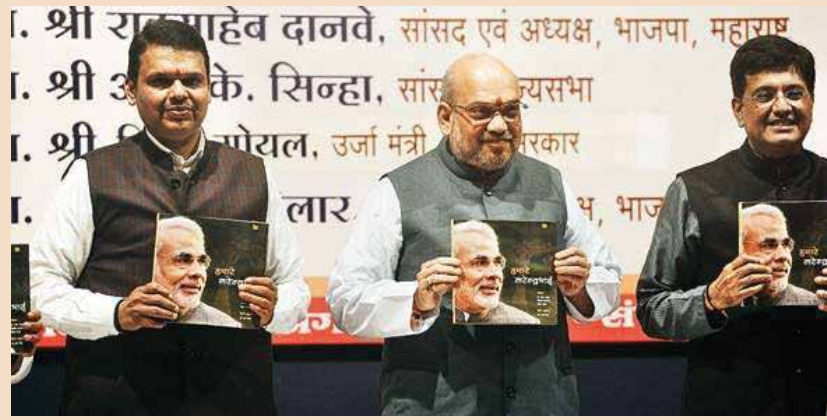

वरिष्ठ पत्रकार श्री किशोर मकवाणा द्वारा लिखित ''हमारे नरेन्द्र मोदी'' गुजराती पुस्तक का विमोचन भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 27 अगस्त 2017 को किया। श्री शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं उनके कार्यों की सराहना की और कहा कि वह आज 'वैश्विक नेता' बन गए हैं। गुजराती में मूल पुस्तक 2016 में प्रकाशित हुई थी और अब इसका अनुवाद हिन्दी में भी उपलब्ध है।

इससे पूर्व, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फड़नवीस, केन्द्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल और भाजपा मुम्बई अध्यक्ष श्री आशीष शेलर ने जनसभा को सम्बोधित किया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यों, उनके विजन तथा मिशन को सराहा।

गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश एवं मेघालय प्रदेश चुनाव प्रभारियों की घोषणा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 24 अगस्त को केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली को गुजरात विधानसभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया। साथ ही, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री पीपी चौधरी को सह प्रभारी बनाया गया।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर को प्रभारी नियुक्त किया गया, साथ ही केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री पीयूष गोयल सह-प्रभारी बनाए गए।

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत को हिमाचल प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया।

वहीं, 6 सितम्बर को केन्द्रीय पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अल्फोंस कनन्नथानम को मेघालय का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया।

गौरतलब है कि चारों राज्यों में विधानसभा चुनाव आसन्न हैं। गुजरात में जहां भाजपा 2001 से सत्ता में बनी हुई है, वहीं हिमाचल, कर्नाटक और मेघालय में कांग्रेस की सरकार है। ■

महेंद्र नाथ पांडेय बने उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 31 अगस्त को केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय को उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। डॉ. महेंद्रनाथ पांडेय चंदौली से 2014 में लोकसभा सदस्य चुने गए थे। उन्हें उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य की जगह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो अभी तक यह प्रभार संभाल रहे थे।

डॉ. महेंद्र नाथ पाण्डेय छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। आपातकाल में डॉ. पाण्डेय पांच महीने के लिए जेल में रहे। राम जन्मभूमि आंदोलन में मुलायम सरकार ने इन्हें रासुका के तहत निरुद्ध कर दिया था। गाजीपुर (सैदपुर) के पखनपुर गांव के मूल निवासी डॉ. पाण्डेय का जन्म 15 अक्टूबर 1957 को हुआ था। एमए, पीएचडी के साथ ही मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की भी डिग्री उन्होंने हासिल की। सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में वह 1973 में छात्रसंघ अध्यक्ष चुने गए। वह 1978 में बीएचयू छात्र संघ के महामंत्री बने। पहली बार 1991 में वह भाजपा के टिकट पर विधायक बने। भाजपा सरकार में डॉ. पाण्डेय नगर आवास राज्य मंत्री, नियोजन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रदेश में वे पंचायती राज मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भी रहे।

प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद डॉ. महेंद्रनाथ पांडेय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने मुझे पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। ये मेरे लिए सम्मान की बात है। यूपी बहुत बड़ा राज्य है इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता होगी पार्टी को और मज़बूत करना। प्रदेश सरकार के कामों के जरिए पार्टी को और ज्यादा मजबूत करना है। ■

1.40 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ अब तक 26 लाख से अधिक मकानों की मंजूरी

शहरी इलाकों में सस्ते मकानों के निर्माण में तेजी आ रही है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों के लिए 2,17,900 और मकानों की मंजूरी दी है, इसके साथ ही 40,597 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता और कुल 1,39,621 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ अब तक 26,13,568 मकानों की मंजूरी दी जा चुकी है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को 41,173 और अधिक मकानों की मंजूरी दी गई है।

नवीनतम मंजूरी में आंध्र प्रदेश को 1,20,894 सस्ते मकान, उत्तर प्रदेश को 41,173, असम को 16,700, गुजरात को 15,222, झारखंड को 14,017 और महाराष्ट्र को 9,894 अतिरिक्त सस्ते मकान मिले हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मंजूर मकानों की संख्या के मामले में शीर्ष 10 राज्यों का विवरण इस प्रकार है:

क्रम संख्या	राज्य	मंजूर किये गए सस्ते मकानों की संख्या	कुल मंजूर निवेश (रुपये करोड़ों)	मंजूर केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	5,41,300	31,056	8,138
2	तमिलनाडु	3,35,039	11,987	5,090
3	मध्य प्रदेश	2,87,101	19,502	4,415
4	कर्नाटक	2,03,260	9,282	3,345
5	गुजरात	1,72,816	11,497	2,493
6	पश्चिम बंगाल	1,44,904	5,920	2,186
7	महाराष्ट्र	1,44,165	15,868	2,244
8	उत्तर प्रदेश	1,20,028	4,767	1,959
9	झारखंड	95,742	3,561	1,474
10	बिहार	88,375	3,915	1,454

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत अब तक मंजूर किये गये कुल 26,13,568 मकानों का 82 प्रतिशत इन दस राज्यों के पास है। दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा और लक्षदीप को छोड़कर सभी 36 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को इस योजना के अंतर्गत मकानों की मंजूरी मिली है। ■

1000 ई-रिक्शा 'स्मार्ट ई' का पहला जत्था गुरुग्राम से रवाना

सड़क परिवहन तथा राजमार्ग, शिपिंग और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 4 सितम्बर को गुरुग्राम के हुडासिटी सेंटर से 1000 ई रिक्शा के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि ई रिक्शा से गुरुग्राम की परिवहन प्रणाली का न केवल कम खर्च में, बल्कि प्रदूषण रहित विकल्प मिलेगा, साथ ही वंचित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि बिजली से सार्वजनिक परिवहन चलाना देश की आवश्यकता है और उनका मंत्रालय इसे शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। ई रिक्शा बेड़े का संचालन स्मार्ट ई ब्रांड के अंतर्गत दिल्ली मेट्रो के साथ साझेदारी में ट्रेजर वेस वेंचर्स प्राइवेट लि. द्वारा किया जा रहा है। स्मार्ट ई से क्षेत्र में अंतिम छोर तक परिवहन संपर्क उपलब्ध होगा। ई रिक्शा भारत में बनाए गए हैं और जीपीएस तथा ट्रैकिंग प्रणाली से लैस हैं। स्मार्ट ई ने हरियाणा सरकार (एचएसआईआईडीसी) तथा दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के साथ साझेदारी में गुरूग्राम और फरीदाबाद में 2017 में 1000 वाहन लांच करेगा। इससे अगले 4-5 वर्षों में एक लाख वंचित युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। ■

अटल पेंशन योजना 62 लाख नामांकन के साथ प्रगति की ओर अग्रसर

एक राष्ट्र-एक पेंशन के अंतर्गत कुल 3.07 लाख अटल पेंशन योजना (एपीवाई) खाते हो गए हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा 30 अगस्त को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार अटल पेंशन योजना के तहत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक भारतीय स्टेट बैंक शामिल है, जिसमें शानदार 51 हजार एपीवाई खाते हैं। अन्य प्रमुख बैंक जैसे केनरा बैंक में 32,306 और आंध्रा बैंक में 29,057 एपीवाई खाते हैं, जबकि अन्य निजी श्रेणी के बैंकों में कर्नाटक बैंक में 2,641 एपीवाई खाते हैं। आरआरबी श्रेणी में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में 28,609 खाते हैं। इसके बाद मध्य बिहार ग्रामीण बैंक में 5,056, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में 3,013, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक में 2,847 और पंजाब ग्रामीण बैंक में 2,194 एपीवाई खाते हैं।

बचत बैंक खातों सहित विभिन्न वित्तीय सुविधाओं पर ब्याज दर कम हो रहा है, ऐसे समय में पेंशन योजना के रूप में अटल पेंशन योजना ग्राहकों के लिए गारंटीड 8 प्रतिशत दर से रिटर्न सुनिश्चित करता है और इस योजना में 20 से 42 वर्ष के लिए निवेश करने पर परिपक्वता के समय रिटर्न दर आठ प्रतिशत से अधिक रहने पर उच्च आय का अवसर भी उपलब्ध होता है। नामांकन बढ़ने से संपत्तियों का वित्तीयकरण होता है और लोग पेंशन सुविधाओं की ओर आकर्षित होते हैं, जो भारत सरकार ग्राहक, उसके जीवन साथी और ग्राहक द्वारा नामित व्यक्ति को निश्चित रिटर्न गारंटी देती है।

पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के सहयोग से वित्तीय सेवा विभाग ने कई एपीवाई अभियान आयोजित किए हैं, जिनके माध्यम से एपीवाई सेवा प्रदाता बैंक और डाक विभाग किसी भी पेंशन योजना के तहत कवर नहीं किए गए लोगों के पास जाकर एपीवाई योजना की विशेषताओं और लाभों की जानकारी देते हैं तथा इस योजना में नामांकन करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं।

पीएफआरडीए ने एपीवाई सेवा प्रदाता बैंकों के साथ मिलकर देश भर में 2 से 19 अगस्त, 2017 तक राष्ट्रीय स्तर पर पेंशन जागरूकता अभियान 'एक राष्ट्र-एक पेंशन' आयोजित किया था। योजना शुरू होने के दो वर्ष बाद अब तक 62 लाख ग्राहक अटल पेंशन योजना के सदस्य बने हैं। पीएफआरडीए का उद्देश्य किसी भी पेंशन योजना के अंतर्गत कवर नहीं किए गए अधिकतम लोगों को एपीवाई योजना के तहत कवर करना है, ताकि भारत एक राष्ट्र के रूप में पेंशन रहित से पेंशन भोगी समाज बने और नागरिक अपनी वृद्धावस्था में सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। ■

प्रधानमंत्री ने किया बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 26 अगस्त को बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके पश्चात् उन्होंने पूर्णिया में राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्षतिपूर्ति, राहत एवं पुनर्वास के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। समीक्षा के पश्चात् प्रधानमंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उन्होंने 500 करोड़ रुपए की तुरंत सहायता की भी घोषणा की।

प्रधानमंत्री ने नुकसान के आकलन के लिए तुरंत ही एक सेंट्रल टीम भेजने का भी आश्वासन दिया है। उन्होंने निर्देश दिया कि किसानों के फसल बीमा के सम्बन्ध में claims का तुरंत आकलन करने के लिए बीमा कम्पनियां अपने पर्यवेक्षक तत्काल प्रभावित क्षेत्रों में भेजें, जिससे किसानों को शीघ्र ही राहत पहुंचाई जा सके।

बाढ़ से प्रभावित सड़कों की मरम्मत के लिए सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को उपयुक्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। बाढ़ से प्रभावित विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर की शीघ्र बहाली के लिए भी केन्द्र, राज्य सरकार की हर संभव मदद करेगा। प्रधानमंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपए की दर से सहायता दी जाएगी।

नेपाल के प्रधानमंत्री श्री शेर बहादुर देउबा की हाल की भारत यात्रा के दौरान उनमें और प्रधानमंत्री मोदी में इस बात पर सहमति बनी है कि सप्तकोसी high dam परियोजना और सुनकोसी storage cum diversion scheme की detailed project report शीघ्र तैयार की जायेगी। दोनों देश सीमावर्ती इलाकों में जलभराव और बाढ़ नियंत्रण पर भी आपस में समन्वय और मजबूत करेंगे। इस से पूरे क्षेत्र में बाढ़ की समस्या से काफी राहत मिलेगी। ■

स्वास्थ्य मंत्रालय ने दो नए गर्भ निरोधकों की शुरुआत की

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय दो नए गर्भ निरोधकों, जिसमें 'अंतरा' कार्यक्रम के तहत इंजेक्शन गर्भनिरोधक एमपीए और गर्भनिरोधक गोली 'छाया' की शुरुआत की है, ताकि दंपतियों की बढ़ती हुई गर्भनिरोधकों की जरूरतों के विकल्पों में विस्तार कर इसे पूरा किया जा सके। ये गर्भ निरोधक वर्तमान में चिकित्सा महाविद्यालयों और जिला अस्पतालों में मुफ्त में उपलब्ध हैं। अब तक 10 राज्यों, जिनमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, दिल्ली और गोवा शामिल हैं, उनमें इनकी शुरुआत की गई है। ये गर्भ निरोधक सुरक्षित और अत्यधिक प्रभावी हैं।

'अंतरा' इंजेक्शन तीन महीनों के लिए कारगर है तथा 'छाया' गोली एक सप्ताह के लिए प्रभावी है। यह दंपतियों की बदलती जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी, जिससे महिलाओं को उनकी गर्भधारण योजना में मदद मिलेगी। सभी राज्यों के स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, जिसमें राज्यों तथा जिला स्तर के डॉक्टर और स्टाफ नर्सों को प्रशिक्षण दिया गया।

गर्भ निरोधकों की आपूर्ति और वितरण में सुधार लाने के लिए मंत्रालय ने हाल में ही एक नए सॉफ्टवेयर फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम (एफपी-एलएमआईएस) की शुरुआत की है, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं तथा गर्भ निरोधकों के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की गई है।

इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने एक केंद्रीय परिवार नियोजन पहल-मिशन परिवार विकास की भी शुरुआत की है। इस पहल का प्रमुख

लक्ष्य बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना तथा गर्भनिरोधकों तक पहुंच में सुधार करना, सुरक्षा सुनिश्चित करना और उच्च गुणवत्ता वाले परिवार नियोजन सेवाओं को बेहतर बनाना है।

यह मिशन देश के उच्चतम प्रजनन दर वाले 146 जिलों में लागू किया जा रहा है। ये जिले उच्च प्रजनन दर वाले इन सात राज्यों- उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और असम में शामिल हैं, जिनका देश की आबादी में 44% योगदान है।

मिशन परिवार विकास परिवार नियोजन पहल का मुख्य उद्देश्य 2025 तक कुल प्रजनन दर को 2.1 तक नीचे लाने का है। अपने निरंतर परिवार नियोजन प्रयासों के माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का उद्देश्य आधुनिक गर्भनिरोधकों के उपयोग को बढ़ाने के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ■

2400 मीट्रिक टन आयातित प्याज पहुंची

अनुचित और अव्यावहारिक व्यापारिक गतिविधियों को रोकने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्यों को प्याज के भंडारन की सीमा लागू करने के लिए कहा है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता मामले विभाग ने वाणिज्य विभाग के साथ मिलकर हाल ही में व्यापारियों/आयातकों के साथ बैठक की। इस बैठक में प्याज के वर्तमान मूल्यों और उपलब्धता स्थिति की समीक्षा की गई।

गौरतलब है कि आयातित लगभग 2400 मीट्रिक टन प्याज पहुंच गयी है, जबकि लगभग 9000 मीट्रिक टन प्याज जल्द ही आने की उम्मीद है। वर्तमान प्याज के उत्पादन से भी पता लगता है कि प्याज के मूल्यों में और वृद्धि का कोई आधार नहीं है। उपभोक्ता मामले विभाग सभी भागीदारों से मिलकर प्याज के मूल्यों की निरंतर समीक्षा करता रहेगा और यदि मूल्यों में अनुचित रूप से वृद्धि होती है तो बाजार में प्याज की पर्याप्त आवक बढ़ाने के लिए निजी व्यापारियों

द्वारा इसके आयात को सरल बनाया जाएगा।

उपभोक्ता मामले विभाग प्याज सहित जरूरी खाद्य वस्तुओं के मूल्यों और उनकी उपलब्धता पर निरंतर नजर रखता है। यह ध्यान दिया गया कि वर्ष 2016-17 के लिए प्याज उत्पादन का तीसरा पूर्व अनुमान पहले के 215.6 लाख मीट्रिक टन उत्पादन की तुलना में बढ़कर 217.2 लाख मीट्रिक टन लगाया गया है। ■

भारतीय जनसंघ की अर्थ नीति

भारतीय जनसंघ उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक सम्मेलन सीतापुर, 1953 के अवसर पर कार्यकर्ता शिविर के लिए दीनदयालजी द्वारा जनसंघ की अर्थ नीति पर लेख।

दीनदयाल उपाध्याय

भारतीय संस्कृति की सदैव से यही मान्यता रही है कि संपत्ति समाज की है। ईशावास्य के प्रथम मंत्र में ही यह मूलभूत प्रश्न पूछा गया है कि संपत्ति किसकी है- 'कस्य स्विद्धनम्।' वस्तुतः संपत्ति के स्वामित्व का प्रश्न मनुष्य समाज के संगठन की एक मुख्य शिला है और शास्त्र में जब यह कहा गया कि 'सुखस्य मूलं धर्मः, धर्मस्य मूलं अर्थ, अर्थ एवं प्रधानः' तब यह स्वीकार कर लिया गया कि सुख और धर्म दोनों के लिए अर्थ का समुचित संतुलन आवश्यक है। तो फिर पुनः यही प्रश्न पैदा होता है कि यह संतुलन किस प्रकार हो। इसके उसी मंत्र में प्रश्न का उत्तर भी देते हुए ऋषि ने असंदिग्ध रूप से यह घोषणा कर दी, हाथ उठाकर यह घोषणा कर दी कि संपत्ति समाज रूप ईश्वर की है।

ट्रस्टीशिप का सिद्धांत

भारतीय संस्कृति के आर्थिक पहलू का नियमन करने वाली यह आद्य और मूलभूत घोषणा है। इसी को आधार मानते हुए समाज के कुछ व्यक्तियों को अथवा एक वर्ग को संपत्ति का ट्रस्टी बनाकर उसके संयम और विनियोग के उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य में पारंगत बनाने की दृष्टि से व्यवस्था की गई और ऐतिहासिक रूप में यह ध्यान देने की बात है कि जब संसार के अन्य देशों, विशेषकर यूरोप में जन-समाज राजाओं तथा सामंतों द्वारा विकृत अर्थव्यवस्था में शोषित हो रहा था, तब भारत में ट्रस्टीशिप के इस सिद्धांत के अंतर्गत संपूर्ण राष्ट्र विविध धन-धान्य से सुखी अपने जीवन को आध्यात्मिक, नैतिक तथा कलात्मक दिशाओं में विकसित करता हुआ जीवनयापन कर रहा था। आज भले ही ट्रस्टीशिप का यह सिद्धांत बिगड़ गया हो और राष्ट्र की संपत्ति के ट्रस्टी व्यक्तिगत सुख-संपन्नता बढ़ाने में ही उसका उपयोग करने लग गए हों, यह निर्विवाद है कि जब तक संपत्ति को समाज की मानने की यह भावना उनमें जीवित रही, तब तक उन्होंने आधी टांगों तक धोती-मिरजई और सिर पर पगड़ी लगाकर ही अपने कर्तव्य का पालन किया और देश को सुख-समृद्धि से भर दिया।

मानव समाज का वर्गीकरण

एक वर्ग को संपत्ति के संचय और विनियोग का समस्त कार्य सौंप देने का कारण यह था कि भारतीय संस्कृति हर व्यक्ति को हर कार्य के उपयुक्त नहीं मानती है। उसने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य समाज के चार भाग किए और वृत्तियों के आधार पर इनमें से एक वैश्य वर्ग को

यह दायित्व दिया। मानव समाज को कुछ भागों में बांटने का यह भारतीय प्रयोग प्रायः सभी देशों में किसी-न-किसी रूप में किया जाता रहा है। अति प्राचीन काल में ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने भी अपनी आदर्श समाज जीवन की कल्पना देते हुए समाज को तीन भागों में बांटने की बात कही थी और आज कम्युनिस्ट देशों में चलने वाला वर्गविहीन समाज का प्रयोग भी उसे तीन वर्गों तक ही बांटकर रह गया है। अतः इन सबसे पहले किया गया भारतीय प्रयोग निस्संदेह विश्व इतिहास की एक सफल व्यवस्था कहा जाएगा। ट्रस्टीशिप की इस व्यवस्था की ओर ध्यान देने योग्य बात यह है कि वह अमर्याद नहीं था। उस पर सदा मर्यादाएं रहीं और इसी कारण वह समाज के लिए लाभकर सिद्ध हुआ। मर्यादित ट्रस्टीशिप अपने शुद्ध रूप में और शुद्ध भावनाओं के साथ चलने पर समाज के कल्याण का कारण होती है। यहां ट्रस्टीशिप से भी अधिक महत्त्व की बात मर्यादा की है। व्यक्ति, निगम या राज्य कोई भी ट्रस्टी हो, यदि वे अमर्याद हुए तो अव्यवस्था शुरू हो जाएगी। कम्युनिस्ट देशों में आज राज्य की अमर्याद ट्रस्टीशिप है और उसके

राजनीतिक दुष्परिणामों से कौन अपरिचित है।

धर्म और श्रम

भारत की वर्तमान परिस्थितियों में जब उसे राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई है, आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने का सवाल खड़ा होता है। यह आज का मुख्य राष्ट्रीय प्रश्न है। इस प्रश्न को हल करने के विभिन्न उद्योग विभिन्न प्रणालियों से तथा विभिन्न दिशाओं में किए जा रहे हैं। हमारे लिए यह प्रश्न इस रूप में आता है कि हम उसको भारतीय ढंग से किस प्रकार हल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि भारतीय ढंग सदा से धर्म का (मज़हब का नहीं) ढंग रहा है और धर्म के इस ढंग पर ही आर्थिक नवनिर्माण के नए नियमों को तैयार करने की जरूरत है। भारतीय वांङमय में धर्म की जो व्याख्याएं समय-समय पर दी गईं, उनमें से सबसे पुरातन होने के कारण वेदों की व्याख्या को हम लेते हैं, जिसमें उसके 12 लक्षण गिनाए गए हैं। इनमें धर्म का आद्य लक्षण सबसे महत्त्वपूर्ण है। (श्रमेण तपसा सृष्टा..) और वह है 'श्रम' । भारतीय ऋषियों ने जीवन में श्रम की अन्यतम महत्ता को भलीभांति जान लिया था और इसीलिए उन्होंने 'श्रम' को धर्म का पहला लक्षण बताया। श्रम की महत्ता का ज्ञान मार्क्स और एंजेल्स के जन्म तक रुका नहीं रहा, वह अति पुरातन काल में सहज अनुभूति से हमने मानवता को दे दिया था।

श्रम का अधिकार (Right to work) मनुष्य का संवैधानिक अधिकार है। राज्य का यह पहला कर्तव्य है कि वह प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार काम करने का अवसर दे। इन अवसरों में किसी प्रकार का भेदभाव, न जाति का, न रंगभेद और न लिंग का होने दें। राष्ट्र के आर्थिक पुनर्निर्माण की जो भी योजना बनाई जाए उसका उद्देश्य सभी व्यक्तियों को काम दिलाना (Full employment) होना चाहिए। भारत की आर्थिक नवरचना के लिए जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई है अथवा भविष्य में इस प्रकार की जितनी भी योजनाएं बनाई जाने की संभावना है, उनका उद्देश्य सभी व्यक्तियों को काम दिलाना ही होना चाहिए।

श्रम मनुष्य का कर्तव्य

आधुनिक शब्दावली में इसी बात को यों कह सकते हैं कि श्रम करना मनुष्य का मूलभूत कर्तव्य है (Duty to work)। इसी प्रकार मनुष्य को श्रम करने का यह अधिकार देना राज्य का भी मूलभूत कर्तव्य हो जाता है। आज जब समाज व्यवस्था बिगड़ी हुई है और श्रम करने वाले मनुष्य को भी, पहले तो उसे श्रम करने का अवसर ही नहीं मिलता, अवसर मिले भी तो उसे भरपेट खाना नसीब नहीं होता, तब राज्य की अपेक्षा में मनुष्य का यह श्रम करने का कर्तव्य कर्तव्य न रहकर अधिकार बन जाता है और इसी अधिकार की मांग, उसकी स्थापना तथा उसी पर आधारित व्यवस्था की रचना ही उसका मुख्य कर्तव्य अथवा परम धर्म बन जाता है।

श्रम का अधिकार

अतः श्रम का अधिकार (Right to work) मनुष्य का संवैधानिक अधिकार है। राज्य का यह पहला कर्तव्य है कि वह प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार काम करने का अवसर दे। इन अवसरों में किसी प्रकार का भेदभाव, न जाति का, न रंगभेद और न लिंग का होने दें। राष्ट्र के आर्थिक पुनर्निर्माण की जो भी योजना बनाई जाए उसका उद्देश्य सभी व्यक्तियों को काम दिलाना (Full employment) होना चाहिए। भारत की आर्थिक नवरचना के लिए जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई है अथवा भविष्य में इस प्रकार की जितनी भी योजनाएं बनाई जाने की संभावना है, उनका उद्देश्य सभी व्यक्तियों को काम दिलाना ही होना चाहिए। इसके बिना ये योजनाएं न राष्ट्रीय कही जा सकती हैं और न भारतीय ही।

जनशक्ति का आधार

इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में जो व्यक्ति काम करेगा, वही खाएगा। काम या श्रम वह है, जिसका परिणाम होता है उत्पादन। लोगों को अधिक-से-अधिक खाने को मिले, अर्थात् राष्ट्रीय वैभव अधिक-से-अधिक बढ़े इसके लिए उत्पादन को अधिक-से-अधिक बढ़ाने की चेष्टा करनी होगी। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जिन साधनों का भी उपयोग करना पड़े, करना चाहिए। लेकिन साधन वाली इस बात की एक मर्यादा है। वह यह कि अपने ही पैरों पर खड़े होने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना चाहिए। विदेशों की सहायता लेकर अर्थात् उनके पैरों पर खड़े होकर चलने का उपक्रम किसी दिन अपने आपको बिल्कुल लंगड़ा बना डालना है और यह गलत मार्ग है। इस दृष्टि से देखने पर लगेगा कि भारत में पूंजी की कमी भले ही हो, जनशक्ति की कमी कदापि नहीं है। उस जनशक्ति को काम का अधिकार (Right to work) देना भी है। अतः जनशक्ति के आधार पर ही अधिक उत्पादन की योजनाएं बनाई जानी चाहिए। कृषि और उद्योग दोनों को ही जनशक्ति के सहारे उठाने की जरूरत है। ■

(क्रमशः)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय

(25 सितम्बर 1916–11 फ़रवरी 1968)

शत–शत नमन !

पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक प्रखर विचारक और उत्कृष्ट संगठनकर्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद जैसी प्रगतिशील विचारधारा दी। उनकी गिनती उन आदर्श महापुरुषों में की जाती है, जिन्होंने आधुनिक राजनीति को शुचिता और शुद्धता के आधार पर स्थापित करने की प्रेरणा दी।

पंडित दीनदयाल एक ऐसे नेता थे, जिन्होंने जीवनपर्यन्त ईमानदारी व सत्यनिष्ठा को महत्व दिया। वे भारतीय जनता पार्टी के लिए वैचारिक मार्गदर्शन और नैतिक प्रेरणा के स्रोत हैं। उपाध्यायजी नितान्त सरल और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे। राजनीति के अतिरिक्त साहित्य में भी उनकी गहरी अभिरुचि थी।

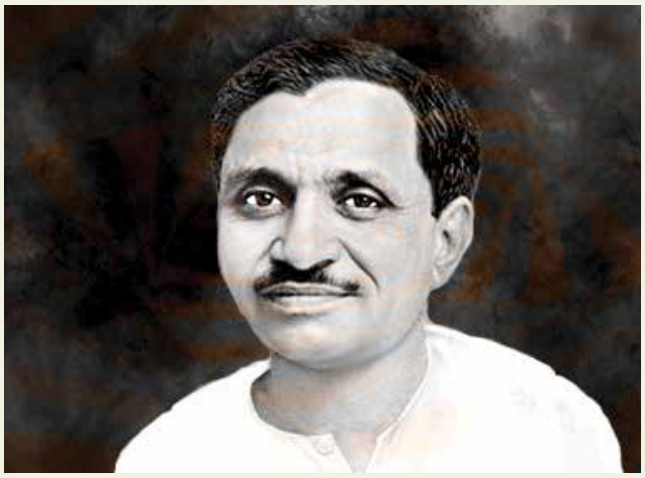

जीवन परिचय

पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर, 1916 को मथुरा ज़िले के छोटे से गांव 'नगला चंद्रभान' में हुआ था। दीनदयाल के पिता का नाम 'भगवती प्रसाद उपाध्याय' था। इनकी माता का नाम 'रामप्यारी' था, जो धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। 7 वर्ष की अवस्था में दीनदयाल माता-पिता के प्यार से वंचित हो गये। सन् 1934 में बीमारी के कारण दीनदयाल के भाई का देहान्त हो गया। उनके मामा राधारमण शुक्ल ने दीनदयालजी को पाला-पोसा।

उपाध्यायजी ने पिलानी, आगरा तथा प्रयाग में शिक्षा प्राप्त की। बीएससी, बीटी. करने के बाद भी उन्होंने नौकरी नहीं की। छात्र जीवन से ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता हो गये। कॉलेज छोड़ने के तुरन्त बाद वे उक्त संस्था के प्रचारक बन गये और एकनिष्ठ भाव से संघ का संगठन कार्य करने लगे। उनका एकात्मवाद सर्वप्रथम 1964 में जनसंघ के ग्वालियर अधिवेशन में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया और अगले वर्ष-1965 में विजयवाड़ा अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने एकात्म मानववाद के सैद्धांतिक विवेचन के बाद कई व्यावहारिक सूत्र भी दिए, जैसे-अर्थव्यवस्था का बुनियादी सूत्र समझाते हुए उन्होंने लिखा था कि रोटी, कपड़ा और मकान जैसी भौतिक जरूरतों की पूर्ति किसी भी अर्थव्यवस्था का न्यूनतम कर्तव्य है।

सन 1951 ई० में भारतीय जनसंघ का निर्माण होने पर वे उसके संगठन मंत्री बनाये गये। दो वर्ष बाद सन् 1953 ई० में उपाध्यायजी भारतीय जनसंघ के महामंत्री निर्वाचित हुए और लगभग 15 वर्ष तक इस पद पर रहकर उन्होंने जनसंघ की अमूल्य सेवा की। दिसम्बर 1967 के कालीकट अधिवेशन में वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 11 फरवरी 1968 को मुगलसराय में उनकी मृत्यु हो गयी।

पं. दीनदयाल उपाध्याय की श्रेष्ठतम वैचारिक देन: एकात्म मानववाद

देश को 'एकात्म मानववाद' का विचार पं. दीनदयाल उपाध्याय की श्रेष्ठतम देन है। यह एक ऐसा चिंतन है, जिसकी जड़ें भारत के अतीत में हैं, पर दृष्टि भविष्य पर। वे इस चिंतन से एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण व विकास करना चाहते थे, जिसके तहत राष्ट्र अपने स्वत्व को ध्यान में रखकर विशुद्ध भारतीय संस्कृति के अनुरूप विकास कर सके।

उनका कहना था कि हमारी संस्कृति और परंपरा में दुनिया को देने योग्य क्या-क्या बातें हैं, उन्हें जानें और विश्व की प्रगति में अपना सहयोग दें। लंबे अरसे तक हमारा सारा ध्यान स्वाधीनता संग्राम व आत्मरक्षा में लगा रहा। अतः हम दुनिया के अन्य राष्ट्रों की बराबरी में खड़े नहीं हो सके हैं, पर आज जब हम स्वतंत्र हैं, तो हमें इस कमी को पूरा करना होगा। इसी वैचारिक पृष्ठभूमि में दीनदयालजी ने 'एकात्म मानववाद' की अवधारणा प्रतिपादित की। यह उनके राजनीतिक चिंतन की उपज है, जिसका केंद्र बिंदु मनुष्य है। मनुष्य का समग्र विकास धर्म का निर्वाह करने पर होता है। मनुष्य का मनुष्य के लिए उनका यह चिंतन राजनीतिक नहीं था। यह उनकी सांस्कृतिक दृष्टि थी, क्योंकि वे भारतीय संस्कृति में प्रगाढ़ आस्था रखने वाले विचारक थे। वे मानते थे कि आर्थिक इच्छाओं की तृप्ति व संतुष्टि कभी भी पूर्ण नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है, तो दूसरी जाग्रत हो जाती है, इसलिए वे कहते थे कि मनुष्य को शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की समन्वित इकाई की तरह ही देखा जाना चाहिए। ■

4 राज्यमंत्रियों को कैबिनेट मंत्री और 9 नए राज्यमंत्री बनाए

गत 3 सितंबर को केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में तीसरा विस्तार एवं फेरबदल किया गया जिसके तहत चार मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर कैबिनेट मंत्री और नौ नये राज्य मंत्रियों को शामिल किया गया। मंत्रिमंडल विस्तार में श्रीमती निर्मला सीतारमण, श्री पीयूष गोयल, श्री धर्मेंद्र प्रधान और श्री मुख्तार अब्बास नकवी कैबिनेट मंत्री बनाए गए।

भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में 3 सितम्बर को मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह के अनुरूप निम्नलिखित को मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया।

कैबिनेट मंत्री- श्री धर्मेन्द्र प्रधान, श्री पीयूष गोयल, श्रीमती निर्मला सीतारमण, श्री मुख्तार अब्बास नकवी। राज्य मंत्री- श्री शिव प्रताप शुक्ला, श्री अश्विनी कुमार चौबे, डॉ. वीरेन्द्र कुमार, श्री अनंत कुमार हेगड़े, श्री राजकुमार सिंह, श्री हरदीप सिंह पुरी, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, डॉ. सत्यपाल सिंह और श्री एलफोंस कन्नथनम।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाले मंत्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके अनुभव एवं बुद्धिमत्ता से उसका महत्व बहुत बढ़ जाएगा। उन्होंने कैबिनेट का दर्जा पाने वाले श्री धर्मेन्द्र प्रधान, श्री पीयूष गोयल, श्रीमती निर्मला सीतारमण और श्री मुख्तार अब्बास नकवी को भी ट्वीट कर बधाई दी।

मंत्रिपरिषद की पूरी सूची इस प्रकार है-

श्री नरेन्द्र मोदी		प्रधानमंत्री एवं प्रभारी :- कार्मिक, जनशिकायत एवं पेंशन परमाणु ऊर्जा विभाग अंतरिक्ष विभाग एवं सभी प्रमुख नीतिगत मामले एवं वे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित न किया गया हो
कैबिनेट मंत्री		
1.	**श्री राजनाथ सिंह**	गृह मंत्री
2.	**श्रीमती सुषमा स्वराज**	विदेश मंत्री
3.	**श्री अरुण जेटली**	वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री
4.	**श्री नितिन जयराम गडकरी**	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, जहाजरानी मंत्री एवं जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री
5.	**श्री सुरेश प्रभु**	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
6.	**श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा**	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री
7.	**सुश्री उमा भारती**	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री
8.	**श्री रामविलास पासवान**	उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री
9.	**श्रीमती मेनका संजय गांधी**	महिला एवं बाल विकास मंत्री

10.	**श्री अनंत कुमार**	रसायन एवं उर्वरक एवं संसदीय कार्य मंत्री
11.	**श्री रविशंकर प्रसाद**	कानून एवं न्याय एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
12.	**श्री जगत प्रकाश नड्डा**	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
13.	**श्री अशोक गजपति राजू पूसापति**	नागरिक विमानन मंत्री
14.	**श्री अनंत गीते**	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री
15.	**श्रीमती हरसिमरत कौर बादल**	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
16.	**श्री नरेन्द्र सिंह तोमर**	ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री एवं खान मंत्री
17.	**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह**	इस्पात मंत्री
18.	**श्री जुएल ओराम**	जनजातीय कार्य मंत्री
19.	**श्री राधा मोहन सिंह**	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
20.	**श्री थावर चंद गहलोत**	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री
21.	**श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी**	कपड़ा मंत्री एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री
22.	**डॉ. हर्षवर्धन**	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, भू-विज्ञान मंत्री एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री
23.	**श्री प्रकाश जावड़ेकर**	मानव संसाधन विकास मंत्री
24.	**श्री धर्मेन्द्र प्रधान**	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री
25.	**श्री पीयूष गोयल**	रेल मंत्री एवं कोयला मंत्री
26.	**श्रीमती निर्मला सीतारमण**	रक्षा मंत्री
27.	**श्री मुख्तार अब्बास नकवी**	अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

1.	**राव इंद्रजीत सिंह**	योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रसायन व उर्वरक राज्य मंत्री
2.	**श्री संतोष कुमार गंगवार**	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
3.	**श्री श्रीपद येसो नाईक**	राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक (आयुष)
4.	**डॉ. जितेन्द्र सिंह**	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जनशिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री एवं अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री
5.	**डॉ. महेश शर्मा**	संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री
6.	**श्री गिरिराज सिंह**	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
7.	**श्री मनोज सिन्हा**	संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रेल राज्य मंत्री
8.	**कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर**	युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री
9.	**श्री राजकुमार सिंह**	बिजली राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
10.	**श्री हरदीप सिंह पुरी**	आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
11.	**श्री अलफोंस कनन्थानम**	पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

1.	**श्री विजय गोयल**	संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री एवं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री
2.	**श्री राधाकृष्णन पी.**	वित्त राज्य मंत्री एवं जहाजरानी राज्य मंत्री
3.	**श्री एस.एस. आहुवालिया**	पेयजल एवं स्वच्छता राज्य मंत्री
4.	**श्री रमेश चंदप्पास जिगाजिनागी**	पेयजल एवं स्वच्छता राज्य मंत्री
5.	**श्री रामदास अठावले**	सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
6.	**श्री विष्णु देव साय**	इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री
7.	**श्री राम कृपाल यादव**	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
8.	**श्री हंसराज गंगाराम अहीर**	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
9.	**श्री हरीभाई पार्थीभाई चौधरी**	खनन मंत्रालय में राज्य मंत्री एवं कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री
10.	**श्री राजेन गोहेन**	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
11.	**जनरल वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त)**	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
12.	**श्री पुरुषोतम रूपाला**	कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री और पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री
13.	**श्री कृष्णपाल**	सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
14.	**श्री जसवंत सिंह सुमन भाई भाभोर**	जनजातीय मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री
15.	**श्री शिव प्रताप शुक्ला**	वित मंत्रालय में राज्य मंत्री
16.	**श्री अश्विनी कुमार चौबे**	स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
17.	**श्री सुदर्शन भगत**	जनजातीय मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री
18.	**श्री उपेन्द्र कुशवाहा**	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
19.	**श्री किरेन रिजिजु**	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
20.	**डॉ. विरेन्द्र कुमार**	महिला व बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री
21.	श्री अनन्त कुमार हेगड़े	कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
22.	श्री एम जे अकबर	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
23.	साध्वी निरंजन ज्योति	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
24.	श्री वाई एस चौधरी	विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री और भू विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री
25.	श्री जयंत सिन्हा	नागरिक विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री
26.	श्री बाबुल सुप्रियो	भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री
27.	श्री विजय सांपला	सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
28.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	संसदीय मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री
29.	श्री अजय टम्टा	कपड़ा मंत्रालय मंत्रालय में राज्य मंत्री
30.	श्रीमती कृष्णा राज	कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
31.	श्री मनसुख एल. मांडविया	सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री और जहाजरानी मंत्रालय में राज्य मंत्री और रसायन व उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
32.	श्रीमती अनुप्रिया पटेल	स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
33.	श्री सी आर चौधरी	उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
34.	श्री पी पी चौधरी	कानून व न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्पोरेट मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री
35.	डॉ. सुभाष रामराव भामरे	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
36.	श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत	कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय राज्य मंत्री
37	डॉ. सत्यपाल सिंह	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री

जन धन योजना और एक अरब-एक अरब-एक अरब 'जैम' (JAM) क्रान्ति का शुभारंभ

जैम की परिकल्पना, वास्तव में इसका लक्ष्य और भी व्यापक था, क्योंकि इसके अन्तर्गत गरीबों की वित्तीय उपेक्षा समाप्त करना प्रमुख था, जिससे उनके जीवन में आर्थिक, डिजिटल और सामाजिक तिरस्कार समाप्त हो। इससे भारत के निर्धनों का आर्थिक शोषण दूर होगा और वे सामाजिक मुख्य धारा का आधारभूत अभिन्न अंग भी बनेंगे।

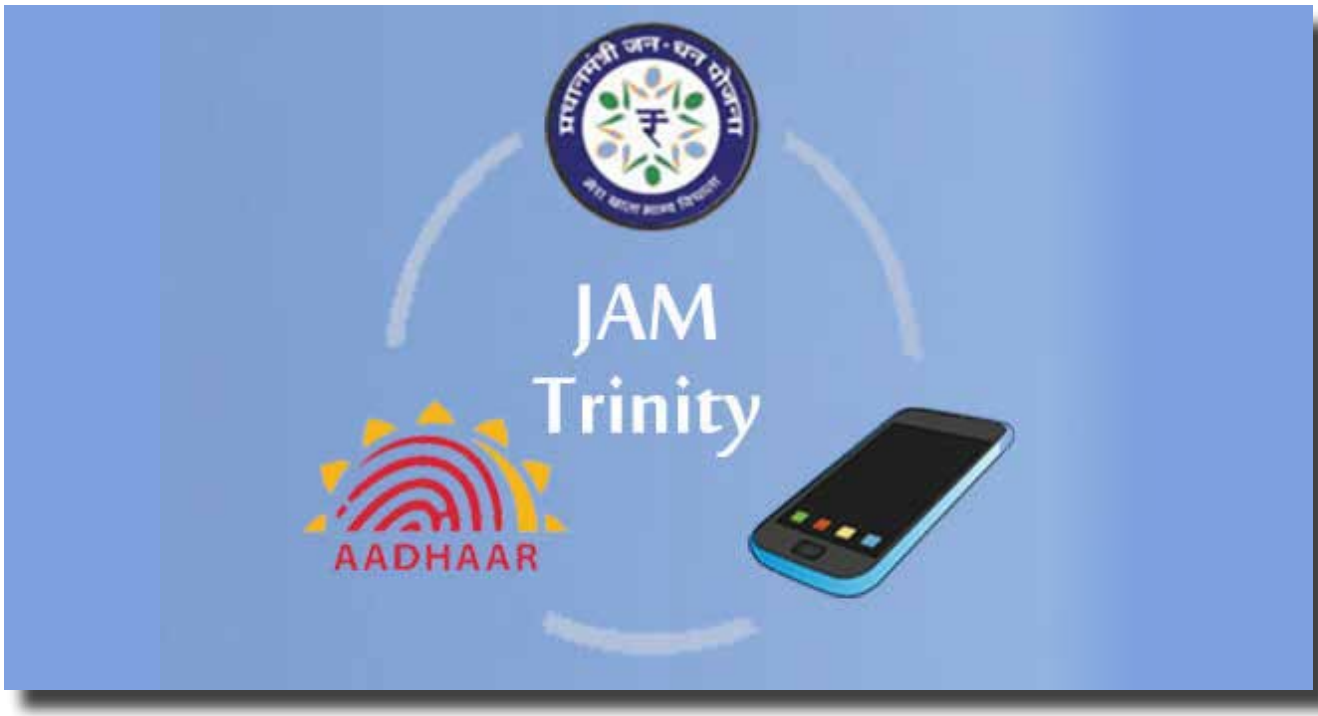

अरुण जेटली

तीन वर्ष पहले आज (28 अगस्त) के दिन प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रमुख कार्यक्रम 'प्रधानमंत्री धन जन योजना' (PMJDY) की घोषणा की, जिसका उद्देश्य गरीबों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। इसके अन्तर्गत गरीबों के लिए बैंक खाते खोलना, उन्हें भुगतान के इलेक्ट्रोनिक साधन (जैसे रुपे RUPAY कार्ड) प्रदान करना तथा उन्हें स्वयं ऋण एवं बीमा प्राप्त करने की स्थिति में रखना शामिल है।

इसकी परिकल्पना, वास्तव में इसका लक्ष्य और भी व्यापक था, क्योंकि इसके अन्तर्गत गरीबों की वित्तीय उपेक्षा समाप्त करना प्रमुख था, जिससे उनके जीवन में आर्थिक, डिजिटल और सामाजिक तिरस्कार समाप्त हो। इससे भारत के निर्धनों का आर्थिक शोषण दूर होगा और वे सामाजिक मुख्य धारा का आधारभूत अभिन्न अंग भी बनेंगे।

उपलब्धियों के तीन वर्ष- कई आयामों के साथ उल्लेखनीय रहे हैं:

1. प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के अन्तर्गत कुल खाते जनवरी 2015 में 12.55 करोड़ से बढ़ाकर 16 अगस्त, 2017 को 29.52 करोड़ खोले गए।
2. प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) अन्तर्गत कुल ग्रामीण खातों की संख्या जनवरी 2015 में 7.54 करोड़ से बढ़कर 16 अगस्त, 2017 को 17.64 करोड़ हुई।
3. रुपे (Rupay) कार्ड जारी करने की संख्या जनवरी 2015 में 11.08 करोड़ से बढ़कर 16 अगस्त, 2017 को 22.71 हुई।
4. लाभार्थी खातों में कुल देय राशि 65,844.68 करोड़ व प्रति खाते में औसत देय राशि जनवरी 2015 में 837 रुपये से बढ़कर 16 अगस्त, 2017 को 2231 रुपये हुई।

5. प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के अन्तर्गत कुल शून्य राशि खातों की संख्या सितम्बर 2014 में 76.81 प्रतिशत से घटकर अगस्त, 2017 में 21.41 प्रतिशत हुई।
6. मार्च 2014 में, 33.69 करोड़ की राशि के साथ महिलाओं के बचत खातों की संख्या 28 प्रतिशत थी। मार्च 2017 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आर.आर.बी (RRB) व 40 शीर्ष बैंकों के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं का योगदान 40 प्रतिशत हो गया। महिलाओं के कुल 43.65 करोड़ खातों में से महिलाओं द्वारा प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अन्तर्गत 14.49 करोड़ खाते खोले गए। यह महिलाओं के वित्तीय समायोजन की बढ़त व तीव्र विकास को दर्शाता है।

वित्त समावेशन के अतिरिक्त सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और दुर्घटना बीमा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के अन्तर्गत गरीबों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं। 7 अगस्त, 2017 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के अन्तर्गत कुल नामांकन 3.46 करोड़ था व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के अन्तर्गत 10.96 करोड़ था इन दोनों योजनाओं में 40 प्रतिशत तक नामांकित महिलाएं हैं।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के सम्पूर्ण ढांचे में मुद्रा योजना (MUDRA YOJANA) के कार्यान्वन को सफल बनाया है। 18 अगस्त, 2017 तक 8.77 करोड़ लाभार्थियों को 3.66 लाख करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। यह राशि उनके बैंक खातों में गई हैं। किन्तु जैसे ये बदलाव आया, प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) व अन्य योजनाएं केवल शुरुआत थी, क्योंकि इन्होंने आगे 'जैम' (JAM) क्रान्ति की शुरुआत की।

(JAM) एक शब्द की रचना व संकल्पित दृष्टिकोण, हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार के अनुसार यह सामाजिक क्रान्ति से कम नहीं हैं, क्योंकि इससे आर्थिक समावेशन प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), बायोमैट्रिक पहचान (आधार) एवं मोबाइल दूरसंचार को एकजुट किया है। आज भारत में लगभग 52.4 करोड़ आधार नम्बर 73.62 करोड़ खातों से जोड़ दिये गए हैं।

भारत के सन्दर्भ में, यह एक अरब-एक अरब-एक अरब दृष्टिकोण कहलाएगा। अर्थात् एक अरब आधार संख्या को एक अरब बैंक खातों व एक अरब मोबाइल फोन से जोड़ा गया है। इस तरह से समूचा भारत आर्थिक (वित्त) व डिजिटल मुख्यधारा का हिस्सा बन सकता है।

इसके परिणामस्वरूप गरीब इलेक्ट्रोनिक भुगतान करने में सक्षम है। अब प्रत्येक माह लगभग 7 करोड़ सफलतापूर्वक भुगतान आधार कार्ड के जरिए गरीबों द्वारा किए जा रहे हैं। सरकार अब 35 करोड़ लाभार्थियों के आर्थिक खातों में वार्षिक 74,000 करोड़ रुपये सीधे स्थानांतरित करती है, जो प्रतिमाह 6,000 करोड़ रुपये से अधिक है। यह स्थानांतरण विभिन्न सरकारी गरीबी उन्मूलन व समर्थन योजनाओं जैसे पहल (PAHAL) मनरेगा (MNREGA) वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension), छात्रवृत्ति इत्यादि के अन्तर्गत की गई हैं।

अब भीम एप (BHIM APP) व Unified Payment Interface (UPI) के साथ, जैम पूर्णतः क्रियाशील हो सकता है। एक सुरक्षित और समेकित डिजिटल भुगतान ढांचे का निर्माण किया गया है, ताकि सभी भारतीय विशेष तौर पर निर्धन डिजिटल मुख्यधारा का हिस्सा बन सकें।

जैम (JAM) सामाजिक क्रांति, सरकार, अर्थव्यवस्था व मुख्यतः गरीबों के लिये वस्तुगत हितलाभ मुहैया कराती है। गरीबों की वित्तीय सेवाओं तक पहुंच रहेगी व जीवन के मुख्य बाधाओं से सावधानी रहेगी। अनुदान के घटने से सरकार के वित्तीय स्थिति सुधरेगी। साथ ही सरकार न्याय संगत व मजबूत होगी, क्योंकि यह नागरिकों को संसाधनों का स्थानांतरण तीव्र व अधिक विश्वसनीयता से सीधे हो सकेगा।

भारत के सन्दर्भ में, यह एक अरब-एक अरब-एक अरब दृष्टिकोण कहलाएगा। अर्थात् एक अरब आधार संख्या को एक अरब बैंक खातों व एक अरब मोबाइल फोन से जोड़ा गया है। इस तरह से समूचा भारत आर्थिक (वित्त) व डिजिटल मुख्यधारा का हिस्सा बन सकता है। जैसे अभी जीएसटी (GST) ने एक कर-एक बाजार-एक भारत की रचना की है, प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) एवं जैम (JAM) क्रांति सभी भारतीयों का एक समान वित्तीय, आर्थिक व डिजिटल समावेशन कर रही है। कोई भी भारतीय मुख्यधारा से अछूता नहीं रहेगा, यह सामाजिक क्रांति से कम नहीं है। ■

(लेखक केन्द्रीय वित्त मंत्री हैं)

जन-धन योजना के तीन वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने सभी लाभकर्ताओं को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 28 अगस्त को जन-धन योजना के तीन वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस ऐतिहासिक वित्तीय समावेशन पहल के सभी लाभकर्ताओं को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा, ''आज, जन-धन योजना ने तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं। मैं उन करोड़ों लोगों, विशेषकर गरीबों को बधाई देता हूं जिन्हें इस पहल का लाभ पहुंचा है। जन-धन क्रांति गरीबों, शोषितों और वंचितों को वित्तीय मुख्यधारा में लाने का ऐतिहासिक आंदोलन है।

जन-धन योजना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, मुद्रा एवं स्टैंड-अप इंडिया के माध्यम से हमने लाखों आकांक्षाओं को पंख दिए हैं। गरीबों और वंचितों के जीवन में गुणात्मक और परिवर्तनकारी बदलाव लाने के हमारे प्रयास असीम शक्ति के साथ जारी रहेंगे।''

ऐसे होगी किसानों की आमदनी दोगुनी

देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किसानों की समग्र भलाई के लिए इस तरह का कोई लक्ष्य देशवासियों के सामने रखा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कृषि मंत्रालय को यह काम 2022 तक अंजाम देना है। कृषि मंत्रालय पूरे मनोयोग और ईमानदारी के साथ प्रधानमंत्री के इस सपने को साकार करने में लगा हुआ है।

| राधा मोहन सिंह |

किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के सामने एक लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य है वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का। देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किसानों की समग्र भलाई के लिए इस तरह का कोई लक्ष्य देशवासियों के सामने रखा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कृषि मंत्रालय को यह काम 2022 तक अंजाम देना है। कृषि मंत्रालय पूरे मनोयोग और ईमानदारी के साथ प्रधानमंत्री के इस सपने को साकार करने में लगा हुआ है। देश के सभी जिलों में 15 अगस्त, 2017 से केवीके के संयोजन में किसानों की आय दुगनी करने के लिए संकल्प सम्मेलनों में बड़ी संख्या में किसान एवं अधिकारी संकल्प भी ले रहे हैं।

2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि मंत्रालय योजनाबद्ध तरीके से 7 सूत्री कार्य योजना पर काम कर रहा है। पहला सूत्र है उत्पादन में वृद्धि, मोटे तौर पर इसका मतलब है पर्याप्त संसाधन के साथ सिंचाई पर ध्यान केन्द्रित करना। यही वजह है कि सर्वप्रथम हमने सिंचाई में बजटीय आवंटन बढ़ाकर इस पर ध्यान केन्द्रित किया है।

भारत के पास 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि है जिसमें से केवल 48 प्रतिशत संस्थागत सिंचाई के तहत है। "हर खेत को पानी' के उद्देश्य के साथ 1 जुलाई 2015 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गयी ताकि सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला, जल संसाधनों, नेटवर्क वितरण और फार्म लेवल अनुप्रयोगों में सर्वांगीण समाधान किया जा सके। हम इसमें समग्र दृष्टिकोण अपना रहे हैं, जो सिंचाई और जल संरक्षण को मिलाता है। उद्देश्य "प्रति बूंद अधिक फसल' पाना है। साथ ही, वर्षों से लम्बित मध्यम एवं बड़ी सिंचाई योजनाओं को 4 वर्षों में प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जल संचयन एवं प्रबंधन के साथ ही वाटर शेड डेवलपमेंट का कार्य भी तेज गति से कार्यन्वित हो रहा है।

दूसरा सूत्र है इनपुट का प्रभावी उपयोग, जिसका अर्थ है गुणवत्तापूर्ण बीज, रोपण सामग्री, जैविक खेती एवं प्रत्येक खेत को मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि। दूसरे सूत्र में हम श्रेष्ठ बीजों एवं पोषकता पर जोर दे रहे हैं। जैविक खेती के लिए भी पहली बार नयी योजना प्रारंभ की गयी है। इसी प्रकार नीम कोटेड यूरिया के माध्यम से यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता तथा यूरिया का अवैध रुप से रसायनिक उद्योग में दुरुपयोग भी समाप्त हो गया है। साथ ही, सॉयल हेल्थ काड्र्स के प्रावधान से संतुलित उर्वरकों के उपयोग के कारण

किसानों की लागत कम हो रही है एवं उत्पादन में बढ़ोतरी भी हो रही है। इसके अतिरिक्त कृषि प्रक्षेत्र में नई तकनीक का उपयोग जैसे-कृषि प्रक्षेत्र के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय कार्यक्रम,किसान कॉल सेंटर, किसान सुविधा एप्पक जैसे दूरसंचार एवं ऑनलाईन माध्यमों से किसानों तक समय सूचना एवं एडवाइजरी भी पहुंचाई जा रही है।

तीसरा सूत्र है उपज के बाद नुकसान कम करना, फसलों की उपज के बाद उसका भंडारण करना किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है। भंडारण की सुविधा के अभाव में मज़बूरी में कम कीमत पर उपज की बिक्री करनी पड़ती है। इसलिए सरकार का मुख्य ध्यान किसानों को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे वेयर हाउस का उपयोग कर अपनी फसल को मजबूरी में ना बेचें। प्राप्त जमा राशि के आधार पर किसानों को बैंकों से ऋण मुहैया कराया जा रहा है, एवं ब्याज में छूट भी दी जा रही है। किसानों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार का पूरा फोकस ग्रामीण भंडारण एवं एकीकृत शीत श्रृंखला (Integrated Cold Chain) पर है।

चौथा सूत्र है गुणवत्ता में वृद्धि, सरकार खाद्य प्रसंस्करण (food processing) के माध्यम से कृषि में गुणवत्ता को बढ़ावा दे रही है। छह हज़ार करोड़ रुपए के आवंटन (allocation) से प्रधानमंत्री

हम किसानों को उनकी भूमि के उस हिस्से का उपयोग करने का प्रोत्साहन दे रहे हैं जो जोता हुआ नहीं है। खासकर खेतों के बीच की सीमा वाला हिस्सा जिसका प्रयोग लकड़ी वाले वृक्ष उगाने एवं सौर सेल बनाने में किया जा सकता है। इसे अतिरिक्त बागवानी, कृषि वानिकी एवं समेकित कृषि पर भी विशेष बल दिया जा रहा है।

किसान संपदा योजना की शुरूआत की गई है। इसके तहत एग्रो प्रोसैसिंग क्लस्टरों के फार्वर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज पर कार्य करके फूड प्रौसेसिंग क्षमताओं का विकास किया जाएगा, जिससे 20 लाख किसानों को लाभ मिलेगा और करीब साढ़े पांच लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

पांचवा सूत्र है विपणन (कृषि बाजार) में सुधार, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मूल्य का बड़ा हिस्सा किसान तक पहुंचे और बिचौलियों की भूमिका न्यूनतम हो। इसके लिए केंद्र सरकार केंद्र सरकार कृषि बाजार में सुधार पर ज़ोर दे रही है। तीन सुधारों के साथ ई-राष्ट्रीय कृषि बाज़ार योजना की शुरूआत की गई है, जिसमें अभी तक 455 मंडियों को जोड़ा जा चुका हैं। कई मंडियों में ऑनलाइन कृषि बाज़ार ट्रेंडिग भी शुरू हो चुकी है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में बाजार सुधार की दिशा में एक मॉडल एपीएमसी एक्ट राज्यों को जारी किया गया है, जिसमें निजी क्षेत्र में मंडी स्थापना, प्रत्यक्ष विपणन मंडी यार्ड के बाहर बनाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त संविदा कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक मॉडल एक्ट बनाने का कार्य भी कर रही है।

साथ ही, किसानों को फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन के रूप में संगठित भी किया जा रहा है, जिससे उन्हे सिर्फ इकोनोमी ऑफ स्केल मिले, बल्कि व्यापारियों के समक्ष उनकी सौदेबाजी शक्ति भी बढ़े। छठा सूत्र है जोखिम, सुरक्षा एवं सहायता, जिसके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। यह किसानों की आय का सुरक्षा कवच है। खरीफ़ व रबी फसल में अब तक की सबसे न्यूनतम दर तय की गई है, जो क्रमशः अधिकतम 2 प्रतिशत और 1.5 प्रतिशत है। इसमें खड़ी फसल के साथ-साथ बुवाई से पहले और कटाई के बाद के जोखिमों को भी शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, नुकसान के दावों का 25 प्रतिशत भुगतान भी तत्काल ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है।

इस योजना में किसानों को फसल नुकसान के त्वरित भुगतान हेतु उपज के अनुमान के लिए ड्रोन तकनीक तथा फसल कटाई के लिए स्मार्ट फोन जैसी नई तकनीकों का उपयोग भी कई राज्यों में प्रारम्भ किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, किसानों की सुविधा के लिए इस खरीफ मौसम से कस्टमर सर्विस सेंटर एवं बैंक आनलाइन जैसी नई तकनीकी सुविधाओं के माध्यम से प्रीमियम राशि जमा कराने का भी प्रावधान किया गया है। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के राहत नियमों में भी सरकार ने बदलाव किए हैं। अब केवल 33 प्रतिशत फसल नुकसान होने पर भी सरकार अनुदान दे रही है। साथ ही अनुदान की राशि को 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है।

जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को भी कम करने के लिए अधिक सहनशीलता वाली किस्मों और पशुओं की प्रजातियों का विकास तथा प्रभावित जिलों के लिए कॉनटिनजेंसी प्लान भी तैयार किए गये हैं। सातवां और अतिंम सूत्र है सहायक गतिविधियों से अर्थात कृषि के अनुसंगी कार्यकलापों जैसे बागवानी, डेयरी विकास, पोल्ट्री, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, कृषि वानिकी,एकीकृत फार्मिंग (Integrated Farming) और रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेंट के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाना। हम सहायक गतिविधियों से किसानों की आय में बढोतरी करेंगे। अंशतः यह मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्यपालन के माध्यम से किया जाएगा। हम किसानों को उनकी भूमि के उस हिस्से का उपयोग करने का प्रोत्साहन दे रहे हैं जो जोता हुआ नहीं है। खासकर खेतों के बीच की सीमा वाला हिस्सा जिसका प्रयोग लकड़ी वाले वृक्ष उगाने एवं सौर सेल बनाने में किया जा सकता है। इसे अतिरिक्त बागवानी, कृषि वानिकी एवं समेकित कृषि पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। ■

(लेखक केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं।)

शासन संचालन में उदाहरणीय परिवर्तन

प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, कौशल विकास, मुद्रा, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, जेएएम तथा डीबीटी जैसे कार्यक्रमों की घोषणा करके विकास की दिशा निर्धारित की। इन कार्यक्रमों को समर्थन देने के लिए उन्होंने आवश्यक नीतियों और सुधारों को लागू किया।

दिलीप कुमार बिसोई

देश ने नरेन्द्र मोदी सरकार 3 साल के कार्यकाल में शासन संचालन में उदाहरणीय परिवर्तन देखा है। नीतियों के साथ सुधारकारी निर्णयों से विकास के लिए देश की मनोदशा में बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को नीतिगत शिथिलता की अवस्था से बाहर निकालने के लिए अनेक सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए। एनडीए सरकार को विरासत में विकास की कम वृद्धि दर उच्च मुद्रास्फीति और उदासीन शासन व्यवस्था मिली थी। निर्यात में गिरावट आने के साथ-साथ औद्योगिक उत्पादन में ठहराव आ गया।

प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, कौशल विकास, मुद्रा, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, जेएएम तथा डीबीटी जैसे कार्यक्रमों की घोषणा करके विकास की दिशा निर्धारित की। इन कार्यक्रमों को समर्थन देने के लिए उन्होंने आवश्यक नीतियों और सुधारों को लागू किया। काले धन को बाहर निकालने के लिए विमुद्रीकरण और माफी योजना से कुछ हद तक अर्थव्यवस्था की साफ-सफाई में मदद मिली। पुराने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन युवा देश और न्यू इंडिया की मांगों और आकांक्षाओं के अनुरूप है।

स्वतंत्रता के बाद उठाये जाने वाले कठोर ऐतिहासिक प्रत्यक्ष कर सुधार 30 जून और 01 जुलाई, 2017 की मध्य रात्रि को वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) लागू करने के साथ शुरू हुआ। जीएसटी व्यवस्था से देशवासी 'एक देश, एक कर' प्रशासन के अंतर्गत आ गए। सुधार का उद्देश्य कर लगाने में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ उपभोक्ताओं, कारोबारियों और उद्योगों के हितों की रक्षा करना है। जम्मू–कश्मीर सहित देश के सभी राज्यों ने प्रत्यक्ष कर सुधार के निर्णय का समर्थन किया। इस निर्णय की सराहना विश्व के अनेक देशों ने की। जीएसटी लागू होने के बाद से सकारात्मक रूझान और देश के अच्छे आर्थिक भविष्य का संकेत मिला है।

मोदी सरकार को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) नीति लागू करने में भारी सफलता मिली है। रसोई गैस के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लागू किया जाना विश्व में सबसे बड़ी डीबीटी योजना है। डीबीटी योजना पहल के अंतर्गत लगभग 15 करोड़ रसोई गैस उपभोक्ता आए हैं। इसे गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉड में दर्ज किया गया है। डीबीटी के कारण चोरी होने वाले 56 हजार करोड़ रुपये के धन की बचत हुई है। एनडीए सरकार ने अब पायलट आधार पर उर्वरक और मिट्टी तेल

सब्सिडी के लिए डीबीटी लागू करने का प्रस्ताव किया है।

पूर्वप्रभाव से कर लगाने की यूपीए सरकार की नीति तथा विभिन्न क्षेत्रों को निवेश के लिए खोलने में शिथिलता के कारण देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिए माहौल खराब हुआ। सत्ता में आने के तुरंत बाद एनडीए सरकार ने विदेश निवेशकों की भावनाओं को समझते हुए घोषणा की कि पूर्वप्रभाव से कर लगाने की नीति सम्बंधित मामलों के अनुसार तय होगी। एनडीए सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति को उदार बनाया और बीमा, रेल, रक्षा तथा खुदरा बाजार जैसे क्षेत्रों में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए अनेक निर्णयों की घोषणा की।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति होगी। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी। इतना ही नहीं 27.08.2014 को जारी डीआईपीपी प्रेस नोट 8 (2014) के माध्यम से रेल क्षेत्र में 100 फीसदी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई। इसी प्रकार डीआईपीपी प्रेस नोट 12 के माध्यम से निर्माण क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर लगे सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया।

एक ही ब्रांड के खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश पर प्रतिबंध को समाप्त करते हुए केंद्र ने सरकारी स्वीकृति मार्ग के जरिए 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी। यह अनुमति इस शर्त के साथ दी गई कि पहले 5 वर्षों में बेचा जाने वाला 30 प्रतिशत माल भारत में तैयार किया जाना चाहिए। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए यह अवधि तीन वर्ष रखी गई। सरकार ने प्रत्यक्ष खुदरा ई-कॉमर्स क्षेत्र में 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश की अनुमति इस शर्त के साथ दी कि जब तक माल एक ही ब्रांड के अंतर्गत नहीं बेचे जाते

और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होते तब तक बिजनेस टू कंज्यूमर ई-कॉमर्स में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं होगी।

एनडीए सरकार ने तेजी से ईंधन मूल्य सुधार का काम किया है। पेट्रोल की कीमतों के विनियमन के बाद से 18 अक्टूबर, 2014 से डीजल की कीमतें भी नियमन दायरे से बाहर कर दी गईं। यही कदम प्राकृतिक गैस के मूल्य के बारे में भी उठाया गया। विकास में खनन क्षेत्र की भूमिका के महत्व को स्वीकार करते हुए मोदी सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए कानूनों और नीतियों को लागू किया। एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन किया गया, ताकि प्रमुख गैर कोयला खनिजों को पट्टे पर देने में पारदर्शिता लाई जा सके। सरकार ने 30 मार्च, 2015 को कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 द्वारा कोयला क्षेत्र को निजी और विदेशी निवेश के लिए खोल दिया। खनन क्षेत्र में पारदर्शी ई-नीलामी से सरकार को बड़ी राजस्व राशि की प्राप्त हुई है।

इसी तरह दूरसंचार स्पेक्ट्रम में पारदर्शिता लाने के लिए परिवर्तन किए गए। भारत ने दूरसंचार क्षेत्र में अनेक स्वतंत्र और निष्पक्ष नीलामी की है और इसे बारे में किसी तरह की शिकायत नहीं मिली। कारोबारी सहजता के हिस्से के रूप में सरकार ने औद्योगिक लाइसेंसों की समाप्ति की तिथि बढ़ा दी है। 20 दिसम्बर, 2014 को डीआईपीपी ने औद्योगिक लाइसेंस की अधिकतम वैधता अवधि 2 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष करने का आदेश जारी किया।

सरकार ने 20 अप्रैल 2015 को क्षेत्रवार निवेश सीमा दूर करते हुए सुरक्षित सूची से अंतिम 20 उत्पादों को हटा दिया। सरकार ने हाल में दिवालियापन कानून लागू किया है, ताकि कम्पनियां आसानी से तरलता की ओर बढ़ सकें।

मोदी सरकार के एजेंडे में अनेक सुधार कार्यक्रम हैं। अब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सब्सिडी खर्च में सुधार करना है। सुधार दीर्घकालिक और निरंतर प्रक्रिया है। शुरू किए गए सुधार कार्यक्रम का असली लाभ अगले दो वर्षों में देखने को मिल सकता है। ■

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार व उड़िया दैनिक समय के सम्पादक हैं।)

भारत नेपाल में बुनियादी ढांचा बनाने और सामाजिक संस्थानों की स्थापना के लिए कटिबद्धः उप-राष्ट्रपति

उप-राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत नेपाल में भौतिक बुनियादी ढांचा बनाने और सामाजिक संस्थानों की स्थापना के लिए कार्य कर रहा है। उप-राष्ट्रपति ने भारत दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री श्री शेर बहादुर देउबा से 24 अगस्त को मुलाकात के दौरान ये बातें कहीं।

उप-राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी बातचीत से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ ही टेराई रोड, रेल लिंक, एकीकृत चेक पोस्टों के साथ ही रक्सौल-आमलेखगंज तेल पाइपलाइन जैसे परियोजनाओं पर भी नए सिरे से ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जलविद्युत क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की भी अपार संभावनाएं थीं और दोनों देशों को 1996 में हस्ताक्षरित पंचेश्वर परियोजना के शीघ्र परिचालन के लिए काम करना चाहिए। इसके साथ जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हमें दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए जल संसाधन क्षेत्र में भी अपने सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है।

उप-राष्ट्रपति ने कहा कि नेपाल अपने सबसे प्रमुख कार्य संविधान को लागू करने और प्रगतिशील एवं समावेशी राजनीतिक एजेंडे को स्थापित करने में है और समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने वाली एक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य में भी लगा है। उन्होंने स्थानीय निकाय चुनावों के दो चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री और नेपाल सरकार को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को नेपाल में आगामी चुनाव में किसी भी चुनाव संबंधी सहायता करने में खुशी होगी।

उप-राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच खुली सीमा होना हमारे संबंधों को विशिष्टता प्रदान करती है और इससे दोनों देशों के लोगों को काफी लाभ भी होता है। उन्होंने चेतावनी दी कि हमें दुश्मनों द्वारा खुली सीमा के दुरुपयोग के प्रति सतर्क भी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल पुलिस और सशस्त्र बल पुलिस को उपकरणों, वाहनों और प्रशिक्षण के माध्यम से सुदृढ़ता प्रदान कर रहा है।

उप-राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सभी पड़ोसी देशों के साथ काम करना चाहता है और हमारी सरकार का प्रयास 'सबका सहयोग, सबका विकास' भारत और भारत के बाहर दोनों जगह लागू होता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत अन्य सभी पड़ोसी देशों के साथ समावेशी विकास प्राप्त करने की इच्छा रखता है। उन्होंने कहा कि भारत नौकरी बढ़ाने तथा सभी पड़ोसी देशों के घरेलू क्षेत्रों की विकास के लिए भी सहायता प्रदान करने को उत्सुक है। ■

सभी देश आतंकवाद से निपटने के लिए समग्र रुख अपनाए

लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद द्वारा की जाने वाली हिंसा पर चिंता

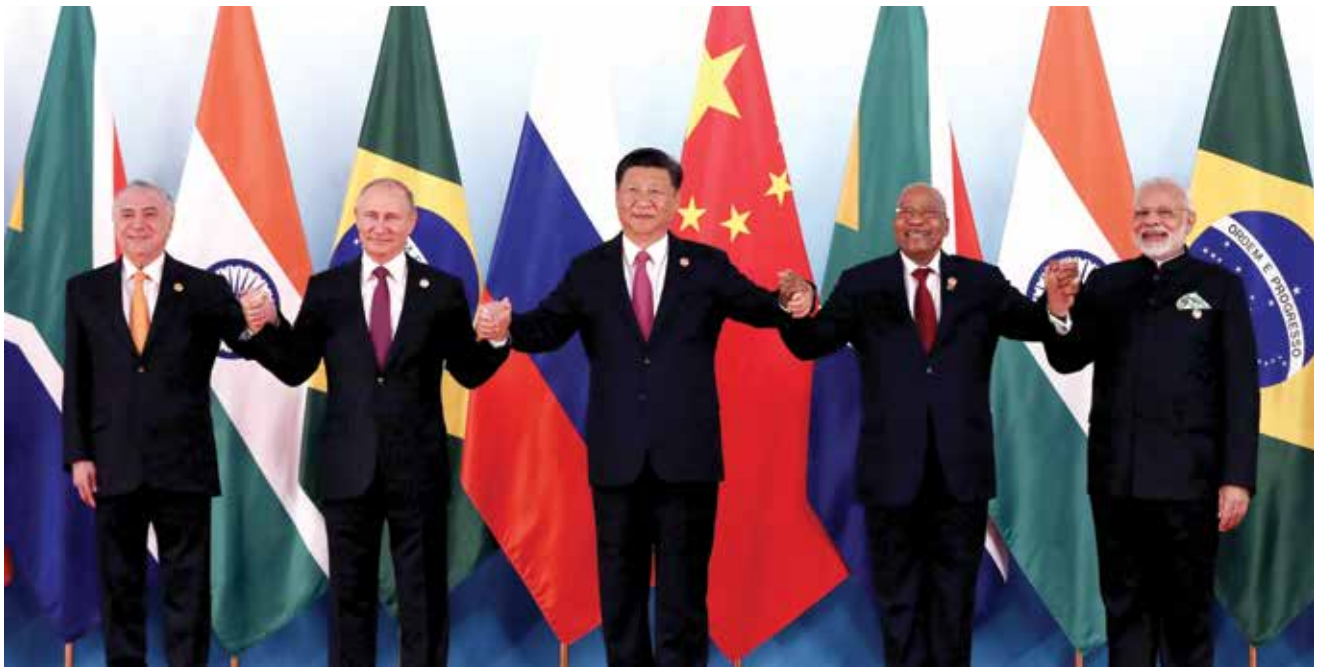

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका यानी ब्रिक्स संगठन के 9 वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। यह सम्मेलन 4-5 सितंबर को चीन के शियामेन शहर में संपन्न हुआ। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेताओं ने आतंकवाद पर चिंता के साथ-साथ खुलेपन, समावेशी और सहयोग की भावना दोहरायी। वे आपस में और अधिक मजबूत और व्यापक रणनीतिक साझेदार संबंधों का निर्माण करने और ब्रिक्स सहयोग का नया दशक शुरू करने की आशा व्यक्त की।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 4-5 सितंबर को चीन के शियामेन शहर में 9 वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन-2017 में हिस्सा लिया। सम्मेलन के दौरान 4 सितंबर को ब्रिक्स नेताओं की उपस्थिति में इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए।

1. आर्थिक और व्यापार सहयोग पर ब्रिक्स एक्शन एजेंडा
2. नवाचार सहयोग (2017-2020) के लिए ब्रिक्स एक्शन प्लान
3. ब्रिक्स सीमा शुल्क सहयोग का कूटनीतिक संरचना
4. ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच समझौता ज्ञापन

आतंकवाद पर चिंता

शिखर सम्मेलन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ने सभी देशों से अपील की कि वे आतंकवाद से निपटने के लिए एक समग्र रुख अपनाए। आतंकवाद से निपटने के क्रम में चरमपंथ से निपटने और आतंकियों के वित्त पोषण के स्रोतों को अवरूद्ध करने की भी बात की गई।

समूह ने क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति के साथ-साथ तालिबान, आईएसआईएस, अल-कायदा और लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद एवं हक्कानी नेटवर्क समेत इसके सहयोगी संगठनों द्वारा की

जाने वाली हिंसा पर चिंता जाहिर की।

भारत ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स बैठक में बोलते हुए कहा कि सभी देशों में शांति के लिए ब्रिक्स देशों का एकजुट रहना जरूरी है। उन्होंने सम्मेलन में आतंकवाद का भी मुद्दा उठाया। इस पर अन्य सदस्य देशों ने भी चिंता जताई।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकास को आगे ले जाने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच मजबूत भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस ब्लॉक ने सहयोग के लिए एक मजबूत ढांचा विकसित किया है और अनिश्चितता की तरफ बढ़ रही दुनिया में स्थिरता के लिए योगदान दिया है। श्री मोदी ने आंतकवाद का भी मुद्दा उठाया। इस पर ब्रिक्स देशों ने क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति और तालिबान, अल-कायदा, पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तैयबा एवं जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी समूहों द्वारा की जा रही हिंसा पर चिंता जतायी।

हम अपने 80 करोड़ युवाओं की ऊर्जा का भी सदुपयोग कर रहे हैं: नरेंद्र मोदी

नौवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पूर्ण अधिवेशन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 4 सितंबर को कहा कि हम गरीबी मिटाने, स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने, कौशल विकास, खाद्य सुरक्षा, लैंगिक समानता, ऊर्जा, शिक्षा और नवोन्मेष की दिशा में मिशन मोड में काम कर रहे हैं। हम स्वच्छ गंगा, अक्षय ऊर्जा, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, सभी के लिए आवास और कौशल भारत के राष्ट्रीय कार्यक्रम और स्वच्छता जैसे कार्यक्रमों के जरिये समावेशी विकास को लेकर आधार तैयार कर रहे हैं।

श्री मोदी ने कहा कि हम अपने 800 मिलियन युवाओं की ऊर्जा का भी सदुपयोग कर रहे हैं। हमारा महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम बहु-उत्पादकता है जिससे राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में महिलाएं भी आ रही हैं। हमने कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कदम उठाए हैं। हमारे इन अनुभवों का ब्रिक्स के सदस्य देश आगे बढ़ते हुए साझेदारी के साथ

लाभ उठा सकते हैं, जिसके परिणाम उत्साहजनक होंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि परस्पर सहयोग के लिए दिमाग में कुछ विचार आए हैं, जिसे मैं यहां साझा कर रहा हूं। पहला, पिछले साल हमने एक ब्रिक्स रेटिंग एजेंसी बनाने की अपनी कोशिशों पर चर्चा की थी। मेरा आग्रह है कि इसे तैयार करने के लिए इसकी रूपरेखा को जल्दी से जल्दी अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। दूसरा, हमारे केंद्रीय बैंकों को अपनी क्षमताओं को और मजबूत करना चाहिए और

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकास को आगे ले जाने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच मजबूत भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस ब्लॉक ने सहयोग के लिए एक मजबूत ढांचा विकसित किया है और अनिश्चितता की तरफ बढ़ रही दुनिया में स्थिरता के लिए योगदान दिया है। श्री मोदी ने आंतकवाद का भी मुद्दा उठाया। इस पर ब्रिक्स देशों ने क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति और तालिबान, अल-कायदा, पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तैयबा एवं जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी समूहों द्वारा की जा रही हिंसा पर चिंता जतायी।

प्रत्यावर्तनीय रिजर्व व्यवस्था और आईएमएफ के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा, हमारे राष्ट्रों के विकास के लिए ऊर्जा की खातिर किफायती, विश्वसनीय और स्थायी पहुंच महत्वपूर्ण है।

वस्तु और सेवा कर भारत में अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार: नरेंद्र मोदी

शियामेन में ब्रिक्स व्यापार परिषद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 4 सितंबर को कहा कि भारत आज दुनिया में तेजी से सबसे ज्यादा खुली अर्थव्यवस्थाओं के रुप में बदल रहा है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रवाह 40 प्रतिशत बढ़ा है और वह अपने उच्चतम स्तर पर है। आसान व्यापार करने के विश्व बैंक की सूचकांक में भारत आगे बढ़ा है। इसी प्रकार, हम पिछले दो वर्षों में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में 32 अंक आगे बढ़े हैं।

श्री मोदी ने कहा कि जुलाई में पेश किया गया वस्तु और सेवा कर भारत में अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है। एक ही झटके में, 1.3 बिलियन लोगों के लिए एक एकीकृत बाजार को निर्माण

कर लिया गया है। डिजिटल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम देश के आर्थिक परिदृश्य को बदल रहे हैं। वे भारत को ज्ञान आधारित, कौशल समर्थित और प्रौद्योगिकी चालित समाज के रूप में बदलने में मदद कर रहे हैं।

हमारे विकास एजेंडे का आधार 'सबका साथ, सबका विकास': नरेंद्र मोदी

शियामेन में 5 सितंबर को आयोजित ब्रिक्स उभरते बाजार एवं विकासशील देश वार्ता में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडे और इसके 17 सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने के दो साल बाद लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साथ मिलकर काम करने की अनिवार्यता अब भी बलवती है। हाल ही में जुलाई में भारत ने एसडीजी की अपनी पहली स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा पूरी की है। हमारे विकास एजेंडे का आधार 'सबका साथ, सबका विकास' - यानी सामूहिक प्रयास, समावेशी विकास की धारणा में निहित है।

श्री मोदी ने कहा कि हमने संघ एवं राज्य दोनों स्तर पर प्रत्येक एसडीजी को अपने विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं के अनुरूप तैयार किया है। हमारी संसद ने भी एसडीजी पर संसदीय चर्चा आयोजित करने की पहल की है। हमारे कार्यक्रम इन प्राथमिकता वाले लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए हम केवल एक उदाहरण का हवाला देते हैं- बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को बैंक खाता खुलवाने, सभी नागरिकों को बायोमेट्रिक पहचान प्रदान करने और अभिनव मोबाइल प्रशासन समाधानों के उपयोग संबंधी हमारे त्रिआयामी दृष्टिकोण से पहली बार करीब 360 मिलियन लोगों तक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पहुंच गया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां उपस्थित देशों में कुल मिलाकर मानवता के लगभग आधे हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम जो भी करेंगे उसका दुनिया पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम ईंट से ईंट जोड़कर यानी ब्रिक्स के जरिये एक बेहतर दुनिया बनाएं। कल मैंने ब्रिक्स को अगले दस वर्षों में वैश्विक परिवर्तन करने के बारे में बात की थी, क्योंकि यह गोल्डन डिकेड है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सुझाव है कि सक्रिय दृष्टिकोण, नीतियों और कार्यों को इन निम्नलिखित दस महान प्रतिबद्धताओं पर लाया जा सकता है:-

एक सुरक्षित दुनिया बनानाः कम से कम तीन मुद्दों- आतंकवाद की रोकथाम, साइबर सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर संगठित एवं समन्वित कार्रवाई।

हरित दुनिया का निर्माणः अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहल के जरिये जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए ठोस कार्रवाई।

एक समर्थ दुनिया बनानाः उपयुक्त तकनीकों को अपनाते और साझा करते हुए दक्षता, किफायती एवं प्रभावकारिता बढ़ाना।

समावेशी दुनिया बनानाः हमारे लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था सहित आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ना।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन की मुख्य बातें

एक सुरक्षित दुनिया बनाना: कम से कम तीन मुद्दों- आतंकवाद की रोकथाम, साइबर सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर संगठित एवं समन्वित कार्रवाई।

हरित दुनिया का निर्माण: अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहल के जरिये जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए ठोस कार्रवाई।

एक समर्थ दुनिया बनाना: उपयुक्त तकनीकों को अपनाते और साझा करते हुए दक्षता, किफायती एवं प्रभावकारिता बढ़ाना।

समावेशी दुनिया बनाना: हमारे लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था सहित आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ना।

डिजिटल दुनिया बनाना: हमारी अर्थव्यवस्था के भीतर और बाहर डिजिटल विभेद को पाटना।

कुशल दुनिया बनाना: हमारे लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करते हुए भविष्य के लिए तैयार करना।

स्वस्थ दुनिया बनाना: सभी लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने और रोगों के उन्मूलन के लिए अनुसंधान एवं विकास में सहयोग करना।

न्यायसंगत दुनिया बनाना: सभी को समान अवसर प्रदान करना खासकर लैंगिक समानता के माध्यम से।

कनेक्टेड दुनिया बनाना: वस्तुओं, व्यक्तियों एवं सेवाओं की मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करना और

सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाना: शांति एवं सह-अस्तित्व पर केंद्रित विचारधाराओं, प्रथाओं और विरासत को बढ़ावा देते हुए प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना।

डिजिटल दुनिया बनानाः हमारी अर्थव्यवस्था के भीतर और बाहर डिजिटल विभेद को पाटना।

कुशल दुनिया बनानाः हमारे लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करते हुए भविष्य के लिए तैयार करना।

स्वस्थ दुनिया बनानाः सभी लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने और रोगों के उन्मूलन के लिए अनुसंधान एवं विकास में सहयोग करना।

न्यायसंगत दुनिया बनानाः सभी को समान अवसर प्रदान करना खासकर लैंगिक समानता के माध्यम से।

कनेक्टेड दुनिया बनानाः वस्तुओं, व्यक्तियों एवं सेवाओं की मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करना और

सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनानाः शांति एवं सह-अस्तित्व पर केंद्रित विचारधाराओं, प्रथाओं और विरासत को बढ़ावा देते हुए प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना। ■

भारत और म्यांमार के बीच कुल हुए 11 समझौते

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6-7 सितम्बर के दौरान म्यांमार की सफल यात्रा की। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और भारत और म्यांमार के बीच कुल 11 समझौते हुए। इन समझौतों में भारत गणतंत्र सरकार और म्यांमार संघ गणतंत्र के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एमओयू, वर्ष 2017-20 के लिए भारत गणतंत्र सरकार और म्यांमार संघ गणतंत्र के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान, येमथिन, म्यांमार में महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के उन्नयन के लिए सहयोग बढ़ाने पर भारत गणतंत्र सरकार और म्यांमार संघ गणतंत्र के बीच एमओयू प्रमुख हैं।

पड़ोसी होने के नाते सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे हित एक जैसे: नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की के साथ मुलाकात करने के बाद साझा प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि पड़ोसी होने के नाते, सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे हित एक जैसे ही हैं। यह ज़रूरी है कि हम अपनी लंबी ज़मीनी और समुद्री सीमा पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर काम करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे दोनों देशों के बीच आज हुए समझौतों से हमारे बहुमुखी द्विपक्षीय सहयोग को और भी बल मिलेगा।

लोगों का सम्पर्क ही भारत–म्यांमार संबंधों की ताकत है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 6 सितम्बर को म्यांमार के यांगून में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित

करते हुए कहा, 'आप हजारों वर्षों की साझा संस्कृति एवं सभ्यता, भूगोल एवं इतिहास, भारत एवं म्यांमार के महान बेटे-बेटियों की आकांक्षाओं एवं उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।'

प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रवासी भारतीय समुदाय भारत के लिए 'राष्ट्र-दूत' जैसा है। उन्होंने कहा कि योग की वैश्विक मान्यता प्रवासी भारतीय समुदाय की उपलब्धि है, जो इसे दुनिया के सभी कोनों में ले जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा, 'जब मैं आपसे मिलता हूं तो मुझे लगता है कि विदेश में रहने वाले हमारे लोगों का भारत के सरकारी अधिकारियों के साथ संचार महज एकतरफा नहीं है।' प्रधानमंत्री ने कहा, 'हम अपने देश में केवल सुधार ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसे बदल रहे हैं।' उन्होंने कहा कि भारत को गरीबी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और जातिवाद से मुक्त बनाया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में केंद्र सरकार बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि अच्छा बुनियादी ढांचा अकेले सड़कों और रेलवे तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसमें कई अन्य पहलू भी शामिल होते हैं जो समाज में गुणात्मक बदलाव लाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कठिन निर्णय लेने से हिचकती नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी देश भर में एक नई संस्कृति का विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को विश्वास है कि भारत को बदला जा सकता है और हम अपनी व्यवस्था में प्रवेश कर चुकी कुछ बुराइयों से मुक्त हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों से लोगों का सम्पर्क ही भारत-म्यांमार संबंधों की ताकत है।

प्रधानमंत्री ने बगान के आनंद मंदिर का दौरा किया

प्रधानमंत्री ने 6 सितम्बर को बगान के आनंद मंदिर का दौरा किया। यह एक बौद्ध मंदिर है जो 12वीं सदी की शुरुआत में बनाया गया था। यह पूरे बगान क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस मंदिर के संरचनात्मक एवं रासायनिक संरक्षण का कार्य किया है। वहां पिछले साल भूकंप से हुए नुकसान के बाद मरम्मत कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री को मंदिर में चल रहे मरम्मत कार्य की फोटो प्रदर्शनी भी दिखाई गई। उन्होंने प्रार्थना के साथ ही मंदिर की परिक्रमा भी की। उस दौरान एएसआई के प्रतिनिधियों ने उन्हें मंदिर के जीर्णोद्धार प्रक्रिया के बारे में बताया।

एएसआई ने एशिया के विभिन्न देशों में कई प्रमुख संरक्षण कार्य किए हैं। आनंद मंदिर के अलावा इसमें अफगानिस्तान के बामियान बुद्ध, कंबोडिया के अंगकोर वाट, लाओस के वाट फोउ मंदिर और वियतनाम के माई सन टेम्पल शामिल हैं।

भारत और म्यांमार के बीच अन्य प्रमुख समझौते

- भारतीय नौसेना और म्यांमार नौसेना के बीच व्हाइट शिपिंग सूचना को साझा करने के लिए एमओयू
- तटवर्ती निगरानी तंत्र उपलब्ध कराने के लिए भारत गणतंत्र सरकार और म्यांमार संघ गणतंत्र के बीच तकनीकी समझौता
- केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत गणतंत्र और खाद्य एवं औषध (एफडीए), स्वास्थ्य एवं खेल मंत्रालय, म्यांमार के बीच चिकित्सा उत्पादों के विनियमन के लिए एमओयू
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत गणतंत्र और स्वास्थ्य एवं खेल मंत्रालय, म्यांमार संघ गणतंत्र के बीच स्वथ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में एमओयू
- एमआईआईटी स्थापना पर एमओयू को बढ़ाने के लिए दस्तावेजों का आदान-प्रदान आईटी-स्किल के संवर्धन के लिए भारत-म्यांमार केंद्र की स्थापना पर एमओयू को बढ़ाने के लिए दस्तावेजों का आदान-प्रदान भारत के निर्वाचन आयोग और म्यांमार के संघीय निर्वान आयोग के बीच निर्वाचन के क्षेत्र में एमओयू
- म्यांमार प्रेस काउंसिल और भारतीय प्रेस परिषद के बीच एमओयू
- आईटी-स्किल के संवर्धन के लिए भारत-म्यांमार केंद्र की स्थापना पर एमओयू को बढ़ाने के लिए दस्तावेजों का आदान-प्रदान

प्रधानमंत्री का म्यांमार स्टेट काउंसिलर आंग सान सू की को उपहार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने म्यांमार स्टेट काउंसिलर आंग सान सू की को उस मूल शोध प्रस्ताव का एक स्पेशियल रिप्रोडक्शन भेंट किया, जो उन्होंने मई 1986 में शिमला में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में अध्येतावृत्ति के लिए प्रस्तुत किया था। शोध प्रस्ताव का शीर्षक था ''दि ग्रोथ एंड डिवलपमेंट ऑफ बर्मीस एंड इंडियन इंटेक्लेक्चुअल ट्रेडिशन्स अंडर कोलोनिएलिज्म': ए कम्पेरेटिव स्ट्डी।'' ■

'स्वच्छता ही सेवा' की मुहिम चलायें: नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 अगस्त को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के दौरान कहा कि तीन वर्ष पूर्व जब स्वच्छता का अभियान प्रारंभ किया था, 2 अक्टूबर को उसको तीन साल हो जायेंगे और उसके सकारात्मक परिणाम नज़र आ रहे हैं। शौचालयों की कवरेज 39% से करीब-करीब 67% पहुंची हैं। 2 लाख 30 हज़ार से भी ज्यादा गांव, खुले में शौच से अपने आपको मुक्त घोषित कर चुके हैं।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि मैं आप सभी से एक आह्वान करता हूं कि एक बार फिर 2 अक्टूबर गांधी जयंती से 15-20 दिन पहले से ही 'स्वच्छता ही सेवा'- जैसे पहले कहते थे 'जल सेवा यही प्रभु सेवा, 'स्वच्छता ही सेवा' की एक मुहिम चलायें। पूरे देश में स्वच्छता के लिए माहौल बनाएं। जैसा अवसर मिले, जहां भी अवसर मिले, हम अवसर ढूंढें, लेकिन हम सभी जुड़ें। इसे एक प्रकार से दिवाली की तैयारी मान लें, इसे एक प्रकार से नवरात्र की तैयारी मान लें, दुर्गा पूजा की तैयारी मान लें। श्रमदान करें। छुट्टी के दिन या रविवार को इकट्ठा हो कर एक-साथ काम करें। आस-पड़ोस की बस्ती में जायें, नज़दीक के गांव में जायें, लेकिन एक आन्दोलन के रूप में करें।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं सभी NGOs को, स्कूलों को, कॉलेज को, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक नेतृत्व को, सरकार के अफसरों को, कलेक्टरों को, सरपंचों को हर किसी से आग्रह करता हूं कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म-जयंती के पहले ही, 15 दिन, हम एक ऐसी स्वच्छता का वातावरण बनाएं, ऐसा स्वच्छता खड़ी कर दें कि 2 अक्टूबर सचमुच में गांधी के सपनों वाला 2 अक्टूबर हो जाए। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, MyGov.in पर एक सेक्शन बनाया है जहां शौचालय निर्माण के बाद आप अपना नाम और उस परिवार का नाम प्रविष्ट कर सकते हैं, जिसकी आपने मदद की है।

उन्होंने कहा कि मेरे सोशल मीडिया के मित्र कुछ रचनात्मक अभियान चला सकते हैं और वर्चुअल वर्ल्ड का धरातल पर काम हो, उसकी प्रेरणा बना सकते हैं। स्वच्छ-संकल्प से स्वच्छ-सिद्धि प्रतियोगिता, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा ये अभियान जिसमें आप निबंध की स्पर्धा है, लघु-फिल्म बनाने की स्पर्धा है, चित्रकला-प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें आप विभिन्न भाषाओं में निबंध लिख सकते हैं और उसमें कोई उम्र की मर्यादा नहीं है, कोई उम्र सीमा नहीं है। आप लघु फिल्म बना सकते हैं, अपने मोबाइल से बना सकते हैं। 2-3 मिनट की फिल्म बना सकते हैं जो स्वच्छता के लिए प्रेरणा दे। वो किसी भी भाषा में हो सकती है, वो मूक भी हो सकती है। ये जो प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे उसमें से जो बेस्ट तीन लोग चुने जायेंगे, जिला स्तर पर तीन होंगे, राज्य स्तर पर तीन होंगे उनको पुरस्कार दिया जाएगा। तो मैं हर किसी को निमंत्रण देता हूं कि आइये, स्वच्छता के इस अभियान के इस रूप में भी आप जुड़ें।

श्री मोदी ने कहा कि मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि इस बार 2 अक्टूबर गांधी जयंती को 'स्वच्छ 2 अक्टूबर' मनाने का संकल्प करें और इसके लिए 15 सितम्बर से ही 'स्वच्छता ही सेवा' इस मंत्र को घर-घर पहुंचायें। स्वच्छता के लिए कोई-न-कोई कदम उठाएं। स्वयं परिश्रम करके इसमें हिस्सेदार बनें। आप देखिए, गांधी जयंती की ये 2 अक्टूबर कैसी चमकेगी। आप कल्पना कर सकते हैं 15 दिन के सफ़ाई के इस अभियान के बाद, 'स्वच्छता ही सेवा' के बाद, 2 अक्टूबर को जब हम गांधी जयंती मनाएगें तो पूज्य बापू को श्रद्धांजलि देने का हमारे भीतर कितना एक पवित्र आनंद होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों गुजरात में भयंकर बाढ़ आई। काफ़ी लोग अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन बाढ़ के बाद जब पानी कम हुआ तो हर जगह इतनी गन्दगी फ़ैल गई थी। ऐसे समय में गुजरात के बनासकांठा ज़िले के धानेरा में, जमीयत उलेमा–ए–हिन्द के कार्यकर्ताओं ने बाढ़-प्रभावित 22 मंदिरों एवं 3 मस्जिदों की चरणबद्ध तरीक़े से साफ़-सफ़ाई की। ख़ुद का पसीना बहाया, सब लोग निकल पड़े। स्वच्छता के लिए एकता का उत्तम उदाहरण, हर किसी को प्रेरणा देने वाला ऐसा उदाहरण, जमीयत उलेमा–ए–हिन्द के सभी कार्यकर्ताओं ने दिया। स्वच्छता के लिए समर्पण भाव से किया गया प्रयास, ये अगर हमारा स्थायी स्वभाव बन जाए तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच सकता है। ■

'एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अधिकतम फायदा पूर्वोत्तर राज्यों को पहुंचाने का प्रयास किया है मोदी सरकार ने'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 5 सितम्बर को नई दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में आयोजित नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस (नेडा) के द्वितीय परिषद् की बैठक को संबोधित किया और नॉर्थ ईस्ट के विकास की प्रतिबद्धता दुहराई।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि नेडा केवल एक राजनीतिक प्लेटफ़ॉर्म भर नहीं है, बल्कि यह पूरे नॉर्थ ईस्ट को सांस्कृतिक रूप से एकजुट करने का एक मंच भी है। उन्होंने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी घोषित किये जाने के बाद अपने पहले ही भाषण में यह स्पष्ट कर दिया था कि देश का विकास समान रूप से नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था कि भारत माता की दो भुजाएं हैं - पश्चिम और पूरब। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा था कि पश्चिम के हिस्से का तो विकास हुआ है, लेकिन पूर्व के हिस्से का विकास नहीं हुआ है और जब तक ईस्ट का विकास जब तक नहीं होगा, तब तक देश का विकास सम्पूर्ण नहीं माना जाएगा। श्री शाह ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 के लोक सभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि यदि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को सरकार बनाने का मौक़ा देती है तो वे नॉर्थ ईस्ट के विकास को प्राथमिकता देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मुझे यह कहते हुए अपार आनंद की अनुभूति हो रही है कि पिछले तीन साल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट के लिए जिस तरह से काम हुआ है, आजादी के 65 सालों में उस तरह से पूर्वोत्तर के विकास के लिए काम कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इसी का परिणाम है कि आज अलग-अलग सांस्कृतिक और जातिगत पहचान रखने वाले नॉर्थ ईस्ट के आठों राज्य नेडा के प्लेटफ़ॉर्म के जरिये भारत का ग्रोथ इंजन बनने के लिए उद्यत हैं। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक और भोगौलिक विविधता से भरे नॉर्थ-ईस्ट को एकजुट रखते हुए पूर्वोत्तर का विकास करना भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है।

श्री शाह ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट की लगभग 4300 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री अलग-अलग देशों के साथ मिलती है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद 65 सालों में नॉर्थ ईस्ट के विकास के साथ-साथ उग्रवाद, घुसपैठ एवं स्मगलिंग की समस्याओं के समाधान के लिए जिस तरह से ध्यान दिया जाना चाहिए था, वह नहीं दिया गया जिसके कारण अपार संभावनाओं के बावजूद नॉर्थ ईस्ट आज भी विकास के मामले में काफी पीछे है। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में पर्यटन की इतनी संभावना भरी पड़ी है कि यह दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है और क्षेत्र के हर युवा को रोजगार मिल सकता है, लेकिन हम इन संभावनाओं को एक्सप्लोर करने में असफल रहे हैं। उन्होंने कहा

कि भ्रष्टाचार के दंश ने नॉर्थ ईस्ट पर इस तरह से अपनी पकड़ जमा ली है कि जितना भी पैसा विकास के लिए भेजा जाता है, विकास होता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट की इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए पिछले तीन साल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार ने कई योजनायें बनाई हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि घुसपैठ, वोट बैंक की राजनीति और उग्रवादी समूहों का राजनीतिक उपयोग - इन तीनों ने नॉर्थ ईस्ट के विकास को डिरेल कर कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा-नीत एनडीए सरकार के लिए नॉर्थ ईस्ट का विकास सर्वाधिक प्रॉयोरिटी वाला कार्य है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट के लिए पॉलिसी में परिवर्तन हुआ है। नॉर्थ ईस्ट को देखने के दृष्टिकोण में बदलाव आया है और क्षेत्रवाद एवं अलगाववाद से ऊपर उठकर समग्र नॉर्थ ईस्ट की विशिष्टताओं को संभाल कर एकात्मकता के भाव के साथ पूर्वोत्तर के विकास पर ध्यान दिया गया है, इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी का उपनाम दिया है। उन्होंने कहा कि डोनर मंत्रालय को प्रो-एक्टिव मंत्रालय बनाकर पूर्वोत्तर के विकास पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि काउंटर इंसरजेंसी के लिए केंद्र सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाये हैं। जहां ऑपरेशन की जरूरत पड़ी, वहां ऑपरेशन किया गया और

जहां संवाद की आवश्यकता आन पड़ी, वहां संवाद भी किया गया। उन्होंने कहा कि 50 साल बाद जब भी नॉर्थ ईस्ट का इतिहास लिखा जाएगा, तब उस का सबसे पहला चैप्टर बांग्लादेश के साथ हुई लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट होने से नॉर्थ ईस्ट के विकास को एक नई दिशा मिली है। उन्होंने कहा कि म्यांमार में सर्जिकल स्ट्रीक करके उग्रवाद पर काबू करने का कठोर संदेश देने का काम किया गया है। इसके साथ-साथ पूर्वोत्तर की सीमा से सटे बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के साथ अच्छे संबंध स्थापित करके भी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मैक्सिमम फायदा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को पहुंचाने का प्रयास किया है।

श्री शाह ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा-नीत एनडीए सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के 13वें वित्त आयोग की तुलना में 14वें वित्त आयोग में मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 258% अधिक धनराशि का आवंटन किया है। उन्होंने कहा कि 13वें वित्त आयोग में नॉर्थ ईस्ट को 87,628 करोड़ करोड़ रुपये मिले थे, जबकि 14वें वित्त आयोग में मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लिए 3,13,375 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मोरार जी देसाई के बाद एनईसी की बैठक में भाग लेने वाले शायद पहले प्रधानमंत्री हैं, इसी से उनकी पूर्वोत्तर के विकास की प्राथमिकता स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने कहा कि हर 15 दिन में केंद्र सरकार के कोई-न-कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट में जरूर होते हैं। पूर्वोत्तर के विकास की मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री जी स्वयं करते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के युवाओं में उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर उद्यम कोष्ठ की रचना की गई है। आईआईएम शिलांग में एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर की स्थापना की गई है। ब्रह्मपुत्र रीजनल स्टडी सेंटर की स्थापना कर इसे गुवाहाटी सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ कर विकास को एक नया आयाम दिया गया है। ऑफ़्रन रोड को प्रायोरिटी के साथ कनेक्टिविटी लिंक बनाने का काम जोरों पर है। सिक्किम को छोड़कर आज पूरा नॉर्थ ईस्ट रेलवे से जुड़ गया है, जेएनयू में पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए अलग से छात्रावास का निर्माण किया गया है। मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों के बीच एयर कनेक्टिविटी पर भी काफी काम किया गया है। उन्होंने कहा कि सिक्किम भारत का सबसे पहला जैविक खेती करने वाला राज्य बना है, जिससे पूर्वोत्तर के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि सिक्किम भारत का पहला ओपन डिफेक्शन फ्री स्टेट बना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आईआईटी गुवाहाटी का उद्घाटन किया गया है, इससे युवाओं के लिए बहुत बड़ी संभावना बनने वाली है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा से बांग्लादेश को जोड़ने वाली रेल लाइन की स्वीकृति देकर केंद्र की भाजपा सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नॉर्थ ईस्ट की दूरसंचार कनेक्टिविटी के लिए लगभग 5,336 करोड़ रुपये की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि 5576 मेगावाट की कुल 16 हाइड्रो पावर योजनाओं को गति देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि माजुली द्वीप के लिए 207 करोड़ रुपया अलग से आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट 2017 में लोगों ने भारी संख्या में पूर्वोत्तर में इन्वेस्टमेंट के लिए रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा वर्ल्ड बैंक की योजनाओं में कैसे शामिल हो सके, इसके लिए भी बहुत अच्छी योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच प्रस्तावित 3200 किलोमीटर की हाईवे योजना पूर्वोत्तर भारत के लिए इन्वेस्टमेंट लाने का एक बहुत बड़ा रास्ता खोलने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए कई महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं, लेकिन यह केवल एक शुरुआत भर है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद 65 सालों तक पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार (अधिकतर समय तक देश में कांग्रेस की सरकार रही) ने नॉर्थ ईस्ट के लिए जो किया है, उससे अनेक गुना काम सिर्फ तीन साल के अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने कर के दिखाया है। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के विकास के हमारे रोडमैप में नेडा अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। उन्होंने कहा कि नेडा केवल एक राजनीति गठबंधन नहीं, बल्कि यह उत्तर पूर्व की सभी सभ्यताओं, संस्कृतियों और विविधताओं को समाहित करते हुए एक सांस्कृतिक मंच भी बने। नॉर्थ ईस्ट की सभी समस्याओं का निराकरण करते हुए एक विकास मंच भी बने, ऐसी हमारी कामना है। उन्होंने कहा कि नेडा के तत्त्वावधान में गुवाहाटी के अंदर नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए एक रिसर्च सेंटर बनाने की परिकल्पना पर तेजी से काम किया जाएगा, जो पूर्वोत्तर के विकास के लिए भारत सरकार में अपनी आवाज बुलंद करेगा। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के सभी जनजातियों का, सभी भाषाओं का सांस्कृतिक संगम हो सके, इसके लिए नेडा के तत्त्वावधान एक सांस्कृतिक मंच भी गुवाहाटी में ही बनाया जाएगा। इसके माध्यम से पूर्वोत्तर के आठों राज्यों में एक सांस्कृतिक एकता का भाव कायम हो सकेगा, साथ ही यह शेष भारत के साथ भी एकात्म भाव से जुड़कर नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए काम हो सकेगा।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नॉर्थ ईस्ट को विकसित देखना चाहते हैं, भ्रष्टाचार से मुक्त देखना चाहते हैं, समृद्ध देखना चाहते हैं और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखते हुए दुनिया भर के पर्यटकों को नॉर्थ ईस्ट में लाने के लिए प्रयास करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को नेडा से भी काफी अपेक्षाएं हैं। उन्होंने कहा कि अभी पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में से पांच राज्यों में नेडा के सदस्य मुख्यमंत्री हैं, मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों में नेडा सरकार बनाने में सफल होगी। ■

15 अगस्त 2022 को सीटी बजा देगी देश की पहली बुलेट ट्रेन

सरकार का कहना है कि देश जब स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, उस वक्त देश की पहली बुलेट ट्रेन अपनी सीटी बजा देगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि अहमदाबाद और मुंबई के बीच 508 किमी लंबे रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए 14 सितंबर को प्रॉजेक्ट का शिलान्यास किया जाएगा। यह सिर्फ रस्म अदायगी नहीं होगी, बल्कि वाकई में उसी दिन से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रॉजेक्ट स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उसी दिन बड़ोदा में इस प्रॉजेक्ट के लिए ट्रेनिंग सेंटर का भी निर्माण शुरू किया जाएगा।

-(नवभारत टाइम्स, 12 सितंबर)

डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में अब तक 17.5 फीसदी की वृद्धि

नोटबंदी और गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (GST) लागू होने के बाद टैक्स कलेक्शन में काफी वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष में अगस्त तक 2.24 लाख करोड़ रुपये डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन हुआ है, जोकि पिछले वर्ष की समान अवधि में प्राप्त टैक्स से 17.5 फीसदी अधिक है। इसके अलावा अप्रैल 2017 से अगस्त 2017 के बीच 74,089 करोड़ टैक्स रिफंड के रूप में दिया गया, जोकि पिछले वित्त वर्ष 2016-17 की समान अवधि से 7.2 फीसदी कम है।

-(नवभारत टाइम्स, 11 सितंबर)

बुलेट ट्रेन प्रॉजेक्ट से हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रॉजेक्ट के शिलान्यास से पहले पीयूष गोयल ने कहा कि मुबंई-अहमदाबाद के बीच शुरू होने वाले इस प्रॉजेक्ट से हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पीयूष गोयल ने मीडिया को बताया, 'इस प्रॉजेक्ट के लिए काफी कम ब्याज दर पर फाइनैंस उपलब्ध करवाया गया है। बुलेट ट्रेन के शुरू होने से देश के रेल नेटवर्क में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है।' रेलमंत्री ने आगे कहा, 'इस हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर के निर्माण से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इससे 4,000 डायरेक्ट जॉब्स और कम से कम 20,000 इनडायरेक्ट जॉब्स के सृजन की उम्मीद है।'

(टाइम्स ऑफ इंडिया, 12 सितंबर)

रोजमर्रा के इस्तेमाल की 40 वस्तुओं पर GST में कमी

जीएसटी काउंसिल की 21वीं बैठक में रोजमर्रा इस्तेमाल की 40 चीजों पर जीएसटी रेट कम करने का फैसला किया है। इसके अलावा छोटी कारों पर जीएसटी दरों को लेकर जीएसटी काउंसिल ने कोई बदलाव नहीं किया है। इस फैसले से आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की बात कही जा रही है। बता दें कि रबड़ बैंड, झाड़ू, सूखी इमली, रेनकोट, कस्टर्ड पाउडर और अगरबत्ती सहित 40 दैनिक उपभोग की चीजों पर जीएसटी दरें कम करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने छोटी कार खरीदने वालों को भी राहत दी है।

-(इकनॉमिक टाइम्स, 10 सितंबर)

स्फुट विचार...

अपने राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत के मूलभूत समस्याओं का प्रमुख कारण है। यह जरुरी है कि हम **'हमारी राष्ट्रीय पहचान'** के बारे में सोचते हैं, जिसके बिना आजादी' का कोई अर्थ नहीं है।

- पं. दीनदयाल उपाध्याय

विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। हमने एकरूपता की नहीं, अपितु एकता की कामना की है। फलतः देश में अनेक उपासना पद्धतियाँ, पंथों, दर्शनों, जीवन-प्रणालियों, भाषाओं, साहित्यों और कलाओं का विकास हुआ, जो सम्पन्नता की द्योतक हैं।

- अटल बिहारी वाजपेयी

अपने देश में अनेकता में एकता की बात सर्वोपरि रही है। भारत एक जन है और यह बात भारतीय जनता पार्टी ने पैदा की हो, ऐसी बात नहीं है। यह तो हजारों वर्षों से, परम्परा से देश का व्यवहार रहा है। आज तो किसी से संपर्क करना बहुत आसान है। पहले ऐसा कुछ नहीं था। पैदल–पैदल जाना होता था। तब भी देश के चारों कोनों में चार पीठ स्थापित हुए। बद्री, केदार से कन्याकुमारी जाओ, यात्रा करो, मिलो–जुलो, यह सारी एकता की भावना भरी थी लोगों में। आज तो इतनी सुविधाएं होने के बावजूद हमें **'एकता परिषद'** बनानी पड़ी है। हमारे देश में एकता की भावना प्राचीन काल से कितनी कूट–कूट कर भरी हुई है, इसका एक अच्छा उदाहरण 1962 के भारत–चीन युद्ध में देखने को मिला।

-कुशाभाऊ ठाकरे

हमारे सम्मानित आजीवन सदस्यगण

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत
श्री अमित शाह
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री अरुण जेटली
केंद्रीय वित्त एवं रक्षा मंत्री
श्री राधा मोहन सिंह
केंद्रीय कृषि मंत्री
श्री प्रकाश जावडेकर
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री जगत प्रकाश नड्डा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
श्रीमती मेनका संजय गांधी
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री
श्री अर्जुन राम मेघवाल
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट राज्यमंत्री
श्री विष्णुदेव साय
केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री
श्री बाबुल सुप्रियो
केंद्रीय भारी उद्योग राज्यमंत्री
श्री मनोहर पर्रिकर
मुख्यमंत्री, गोवा

श्री भूपेन्द्र यादव, सांसद
भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री
श्री अरुण सिंह
भाजपा राष्ट्रीय महासचिव
श्री शांता कुमार, सांसद
पूर्व मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश
श्री गोपाल नारायण सिंह
सांसद (राज्यसभा)
डॉ. गोकाराजू गंगा राजू
सांसद (लोकसभा)
श्री महेश पोद्दार
सांसद (राज्यसभा)
श्री अनिल शिरोले
सांसद (लोकसभा)
श्री मनोज राजोरिया
सांसद (लोकसभा)
श्री रवींद्र कुमार राय
सांसद (लोकसभा)
श्री दिलीप कुमार गांधी
सांसद (लोकसभा)
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल
राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

नौवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शियामेन, चीन में उभरते बाजारों और विकासशील देशों के संवाद पर वक्तव्य देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

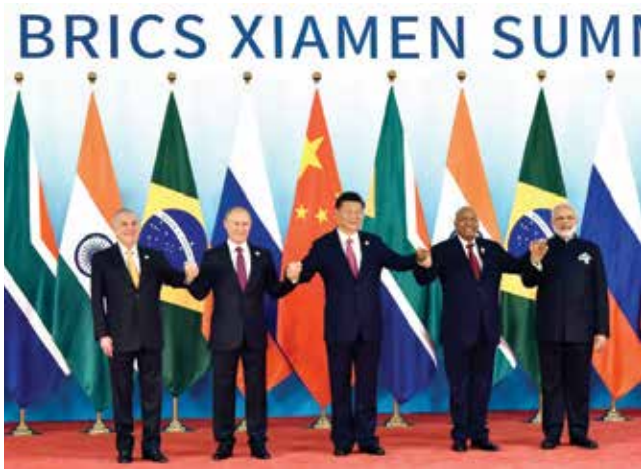

शियामेन, चीन में नौवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अन्य ब्रिक्स नेताओं के साथ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नाएप्यीडॉ, म्यांमार में म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की के साथ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी म्यांमार के यांगून स्थित श्वेदागोन पगोडा जाते हुए

म्यांमार के यांगून स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा–अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2015-17
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2015-17